● वर्ष-5
● अंक-276
रायपुर, रविवार
05 जुलाई 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> सभी विस्थापितों को मिलेगा ...

भारत सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उबरा: प्रधानमंत्री मोदी

भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र कर कहा कि इस संकट के समय भारत की कूटनीतिक शक्ति का जलवा दुनिया को दिखा, इस शक्ति ने देश को चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की।

पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा किया था। इस चुनौती के बावजूद, भारत ने सही फैसलों, सटीक आकलन, प्रभावी रणनीति और कूटनीतिक शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक स्थिति संभाली। उन्होंने कहा कि संकट से पहले भारत 25-26 देशों से ईंधन आयात करता था, लेकिन युद्ध के दौरान भारत की कूटनीति के

कारण यह संख्या 40 से अधिक देशों तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि उसके लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, उन पर ईंधन संकट के बीच अफवाहें फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत इरादे वाले सफल नहीं हुए और देश में दूर-दराज के इलाकों में भी छोटी-मोटी अड़चनों के अलावा ईंधन आपूर्ति में कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा कि जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थीं, तब पर्दे के पीछे किस स्तर पर दिन-रात काम हो रहा था और स्थिति को संभाला जा रहा था, यह कभी न कभी इतिहास में लिखा जाएगा। अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहकर अफवाहों, डर और भ्रम फैलाने वालों की साजिशों को नाकाम किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों के इसी विश्वास के भरोसे देश आगे बढ़ रहा है।

पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकारें परियोजनाओं का शिलान्यास करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़तीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात काम करती हैं। उन्होंने दो महीने पहले रिफाइनरी में हुए हादसे के बाद भी इतनी तेजी से काम पूरा करने की सराहना की, यह दिखाता हैं कि नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पीएम मोदी ने देश की दृढ़ शक्ति को रेखांकित कर कहा कि इस कारण सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो गया और भारत ने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर जोर देकर कांग्रेस सरकारों पर राजस्थान के जल संकट को दूर करने में ठोस काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान को बिना किसी विवाद के नर्मदा का पानी साझा करने का उदाहरण दिया, यह दर्शाते हुए कि भाजपा क्षेत्रवाद और बंटवारे की राजनीति नहीं करती।

भारत-इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

एफटीए पर चल रही चर्चा

- **समझौते में पोर्टफोलियो निवेश भी शामिल किया गया है।**
- **इजरायल पहला ओईसीडी सदस्य जिसके साथ यह समझौता।**

नई दिल्ली। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआइए) शनिवार से लागू हो गया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश वातावरण सुनिश्चित करेगा।

साथ ही सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होगी। दोनों देशों ने इस समझौते पर पिछले वर्ष आठ सितंबर को हस्ताक्षर किए थे। मंत्रालय ने बताया कि समझौते के तहत भारत ने इजरायली निवेशकों के लिए स्थानीय उपायों की समाप्ति अवधि को तीन वर्षों तक सीमित कर दिया है।स्थानीय उपायों का मतलब है कि निवेशकों को पहले मेजबान देश की कानूनी प्रणाली का उपयोग करके अपने विवादों को हल करने का प्रयास करना होगा। इसके बाद ही वे वे मामले को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में ले जा सकेंगे।सामान्य तौर पर भारत के लिए यह अवधि पांच वर्ष होती है। भारत-इजरायल बीआइए में पोर्टफोलियो निवेश भी शामिल है, जो पिछले ऐसे समझौतों से बिलकुल अलग है।

इजरायल पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सदस्य है, जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया है। अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत को इजरायल से 37.13 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) मिला है।आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआइ) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि इजरायल के साथ ताजा समझौते में पोर्टफोलियो निवेश को शामिल करने से पारंपरिक एफडीआइ अलग कुछ वित्तीय निवेशों को बढ़ा सकता है। पोर्टफोलियो निवेश में शेयर, स्टाक व अन्य इक्विटी होल्डिंग, योग्य बांड, डेट और अन्य कारपोरेट ऋण शामिल हैं।

एफटीए पर भी वार्ता कर रहे दोनों देश

इस समझौते का लागू होने इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, पश्चिम एशिया संकट के कारण एफटीए वार्ता की गति धीमी है।

भारत अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय निवेश समझौतों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

रायपुर। चिंतन शिविर 3.0 का उद्देश्य शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी नीति-निर्माण की मजबूत आधारशिला तैयार करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शासन के विभिन्न आयामों पर व्यापक मंथन करते हुए यह बात कही।

>>विस्तृत समाचार पेज-8 पर

परिसीमन बिल की गहमागहमी के बीच होगा मानसून सत्र

नई दिल्ली। लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ करने के सियासी दांव-पेंच के बीच सरकार ने 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र बुलाने का एलान कर दिया है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले इस सत्र को लेकर राजनीतिक गहमागहमी पहले से ही शुरू हो गई है क्योंकि सरकार महिला आरक्षण तथा परिसीमन संबंधी संविधान संशोधन बिल दुबारा लाने की तैयारी में जुटी हुई है।

शिवसेना यूबीटी के नौ में से छह सांसदों के पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने तथा तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सांसदों के टूट कर अलग गुट बनाने तथा

भाजपा-एनडीए सरकार का समर्थन करने के एलान के बाद मानसून सत्र में नए सिरे से परिसीमन बिल लाए जाने की चर्चाएं गरम है।संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को एक्स पोस्ट पर सत्र की तारीखों का एलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को मानसून सत्र 2026 के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है।20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। मानसून सत्र परिसीमन बिल के संदर्भ में निर्णायक हो सकता है और कुछ दिन पहले रिजिजू ने भी इस संदर्भ में सरकार के आगे बढ़ाने के इरादे जाहिर किए थे।मालूम हो कि बीते अप्रैल में सरकार ने बजट सत्र का सत्रावसान नहीं कर बंगाल चुनाव के बीच महिला आरक्षण तथा परिसीमन बिल पारित कराने के लिए चार दिनों का सत्र बुलाया था।

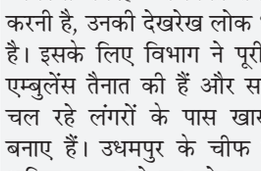

20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा : रिजिजू

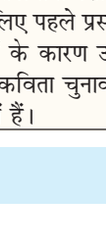

नईदिल्ली। अप्रैल में संसद की

पिछली बैठक के बाद से राजनीतिक हालात में काफी बदलाव आया है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में सदन के भीतर नया राजनीतिक समीकरण और बदली हुई केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसमें सदन की बनावट में कुछ बेहद चौंकाने वाले और दूरगामी बदलाव शामिल होंगे।

प्रमुख समाचार

अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी ने ट्रंप को दी बधाई

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के और बढ़ने को लेकर आशा व्यक्त की। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच दोस्ती वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, 1.4 अरब भारतीयों की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को आपकी स्वतंत्रता की ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक रणनीतिक साझेदारी से कहीं बढ़कर हैं और कहा कि लोकतंत्र, कानून के शासन और दोनों देशों के लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास इस दोस्ती को वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बनाता है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 250 साल अमेरिका के लिए और भी अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लाएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।

बंगाल टीएमसी चीफ चंद्रिमा ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी से नेताओं के लगातार बाहर जाने के बीच यह कदम उठाया गया है। ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी चंद्रिमा को मई में

विधानसभा चुनावों में टीएमसी को भारी नुकसान होने के बाद पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हार के बाद, ममता ने पार्टी की सभी मौजूदा कमेटियों को भंग कर दिया और संगठन का पुनर्गठन किया। टीएमसी दो गुटों में बंट गई - एक गुट का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही थीं और दूसरे का राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रिताब्रत बनर्जी। इस बीच, टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (जो बहुत कम जानी-पहचानी पार्टी है) में शामिल हो गए और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को समर्थन देने का वादा किया।

महाराष्ट्र में भी यूसीसी लाने की तैयारी तेज

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार पहले एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी, जो मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर महाराष्ट्र के लिए

यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान समिति के गठन की घोषणा अगले सप्ताह की जा सकती है। इस फैसले के बाद राज्य में यूसीसी को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार राज्य विधानसभा में विधेयक लाने से पहले विशेषज्ञ समिति गठित करेगी। यह समिति मौजूदा कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी, जरूरी दस्तावेजों की समीक्षा करेगी और महाराष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य के लिए ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है, जिसे आगे विधानसभा में पेश किया जा सके। समिति के गठन की घोषणा अगले सप्ताह किए जाने की संभावना है।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने सफल अमरनाथ यात्रा की कामना की

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में चल रही सालाना अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पुष्टि की कि उनके प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और मदद के लिए सभी ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रद्धालुओं को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि हमें उम्मीद है कि तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आएंगे। उनकी यात्रा अच्छी रहे और वे सुरक्षित घर लौटें। सरकार की तरफ से जो भी इंतज़ाम किए जाने थे, वे हमने कर लिए हैं। बाकी चीज़ें - जैसे सुरक्षा, कानून-व्यवस्था वगैरह - जिनकी तैयारी श्राइन बोर्ड को करनी है, उनकी देखरेख लोक भवन से की जा रही है। इसके लिए विभाग ने पूरी तरह से लैस छह एम्बुलेंस तैनात की हैं और समरोली में पहले से चल रहे लंगरों के पास खास मेडिकल स्टेशन बनाए हैं। उधमपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल मन्हास ने,ह्व को बताया कि तीर्थयात्रियों को तुरंत मदद देने के लिए लंगरों के साथ 10 जगहों पर फर्स्ट-एड कैंप लगाए गए हैं।

टीआरएस नाम को लेकर फंसा पेंच के कविता को ईसीआई का नोटिस

नईदिल्ली। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने के. कविता को उनकी प्रस्तावित पार्टी के नाम टीआरएस पर आपत्तियों के बाद नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई 4 जुलाई को तब की गई जब आयोग को 1,100 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं। इनमें से एक शिकायत कथित तौर पर भारत राष्ट्र समिति

(बीआरएस) ने कविता की प्रस्तावित पार्टी के नाम और बीआरएस की पुरानी पहचान के बीच समानता को लेकर दर्ज कराई थी। कविता ने शुरू में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र सेना (टीआरएस) रखने की घोषणा की थी। हालाँकि, चुनाव आयोग (ईसीआई) ने उन्हें सलाह दी कि वे कोई दूसरा नाम चुनें ताकि पुरानी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) -जिसका नाम बाद में बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया गया था- के साथ कोई भ्रम न हो। चुनाव आयोग की सलाह मानते हुए, कविता ने पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना रक्षा सेना कर दिया। इसके बावजूद, पार्टी के लिए पहले प्रस्तावित नाम को लेकर मिली कई शिकायतों के कारण उन्हें नोटिस भेजे गए। सूत्रों के अनुसार, कविता चुनाव आयोग के रुख को मानने को तैयार नहीं हैं।

परिवर्तन की जड़ें: ई-गवर्नेंस से बदलता ग्रामीण भारत

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

कुछ क्षण केवल एक उपलब्धि भर नहीं होते, वे एक पूरी यात्रा को रोशन कर देते हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चार पंचायती राज पहलों का चयन ऐसा ही एक क्षण है, ऐसा क्षण जो किसी एक कार्यालय का नहीं, बल्कि हर ग्राम पंचायत और हर उस नागरिक का है, जिसने डिजिटल रूप से सशक्त ग्रामीण भारत के सपने पर भरोसा किया है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर, भारत की पंचायतें भरोसे, तकनीक और परिवर्तन का एक नया अध्याय लिख रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के बारह परिवर्तनकारी वर्षों के इस पड़ाव पर यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं मात्र योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित निकायों से आगे बढ़कर, शासन की तीसरी स्तरीय व्यवस्था की आत्मविश्वासी, सक्षम और तकनीकी रूप से दक्ष संस्थाओं के रूप में स्थापित हुई हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्कृष्ट लोक सेवा वितरण के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष सात श्रेणियों में चयनित 17 परियोजनाओं में से 4 पंचायती राज क्षेत्र से संबंधित हैं, जो ज़मीनी स्तर पर नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु पिछले बारह वर्षों के निरंतर प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम है। ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख पहल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स , को डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के आने से पहले, देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कोई मानकीकृत, डेटा आधारित राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध नहीं था। आज यह सूचकांक डेटा, प्रदर्शन, पहचान और जनभागीदारी को आपस में जोड़ने वाली एक पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। उल्लेखनीय यह है कि दो ग्राम पंचायतों ने अपने स्वयं के प्रयासों से यह सम्मान अर्जित किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडेपुर ग्राम पंचायत ने ग्रासरूट स्तर की पहलों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से 1,300 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं, पश्चिम त्रिपुरा की बिजय नगर ग्राम पंचायत को रजत पुरस्कार मिला है। पंचायत ने अपने स्वयं के स्रोतों से आय में लगभग 194 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और महिलाओं के बीच शत-प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल की है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग को 'ई-आरोग्य धमनी' पहल के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया। ये पुरस्कार मिलकर एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता अब केवल राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समान रूप से हमारे गांवों और ग्राम सभाओं में भी स्थापित हो चुकी है। इस वर्ष 30 राज्यों की 1.65 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया, जो हमारे द्वारा मिलकर तैयार की गई संस्थागत क्षमता और विश्वास को दर्शाता है। यह उपलब्धि संयोग से नहीं मिली है। पिछले बारह वर्षों में मंत्रालय ने पंचायतों को निरंतर बेहतर साधन उपलब्ध कराए हैं। ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.59 लाख से अधिक पंचायतों में योजना निर्माण, बजट और भुगतान प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से 3.16 लाख करोड़ से अधिक के ऑनलाइन लेन-देन संभव हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सभासार प्लेटफॉर्म, जो 23 भारतीय भाषाओं में कार्य करता है, अब 1.35 लाख से अधिक पंचायतों में चंद मिनटों में ग्राम सभा की कार्यवाही तैयार कर देता है। मेरी पंचायत ऐप, जिसे 1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, विकास कार्यों की जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुंचा रहा है। इन प्रयासों के साथ-साथ, स्वामित्व योजना के तहत 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है तथा जून 2026 के मध्य तक 1.94 लाख गांवों के लिए 3.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकार सुदृढ़ हुए हैं और उन्हें ऋण सुविधा प्राप्त करने में आसानी हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.82 लाख करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है। सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 से 2031 के लिए 4.35 लाख करोड़ की सिफारिश की है, जो लगभग 84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने सेवा से समृद्धि- पंचायतों के नेतृत्व में सेवा वितरणविषय पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। इन कार्यशालाओं में पंचायत प्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी और विषय विशेषज्ञ मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में लोगों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के उपायोंपर चर्चा कर रहे हैं।

कर्ज में डूबा महिला समूह: गोबर पेंट के लिए नहीं मिल रहा कोई खरीदार

मोहला-मानपुर। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन शुरू की थी ताकि महिलाएं और महिला समूहें योजना से लाभान्वित होकर आर्थिक आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन विडंबना ही कहें कि मोहला-मानपुर जिले में हरूरू विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये और जिला प्रशासन की बेपरवाही ने स्व रोजगार के वरदान के तौर पर शासन द्वारा धरातल में उतारी गई ये योजना आदिवासी बाहुल्य इलाके के महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई है। कांग्रेस सरकार में जिस गोबर का बोलबाला था सत्ता परिवर्तन के बाद आज यही गोबर महिलाओं के लिए मुसीबत बन गई है और उनका समूह कर्ज में डूब गया है। दरअसल, मानपुर विकासखंड अंतर्गत औंधी तहसील क्षेत्र के ग्राम सरखेड़ा में संचालित पदम महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हरूरू के तहत प्रशासनिक अफसरों के भरोसे गोबर पेंट का रोजगार अपना कर

लाखों रुपए के कर्ज में डूब गई हैं। समूह की महिलाओं की माने तो प्रशासनिक अफसरों ने उन्हें गोबर पेंट का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि बनाए गए गोबर पेंट को बिकवाने में वे समूह की मदद करेंगे। यही नहीं शासकीय दफ्तरों में भी उपयोग किए समूह से गोबर पेंट की खरीदी होगी। महिलाओं के मुताबिक, अफसरों के इस भरोसे को आधार बनाकर उन्होंने शासन द्वारा सरखेड़ा गांव में स्थापित रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क परिसर में यहां लगे पेंट निर्माण संयंत्रों के जरिए भारी मात्रा में गोबर को फिल्टर कर उससे प्राकृतिक पेंट का बनाया। महिलाओं की मानें तो बैंक से लाखों रुपए लोन लेकर समूह ने करीब 12 लाख रुपए की लागत का गोबर पेंट बनाया, मार्केट से डिब्बे खरीदकर पेंट का पैक तैयार किया गया, लेकिन अब बिक्री न होने के चलते पेंट की खेप रीपा केंद्र में धूल फांकते पड़ी है।शुरुआती दौर में करीब 3 लाख 50 हजार रुपए का पेंट बिका जरूर लेकिन अब तक केवल 50 हजार रुपए ही भुकतान ही उन्हें मिल सका है। महिलाओं के मुताबिक एक तरफ तीन लाख रुपए का भुगतान अटका है, पेंट की बिक्री न होने से वे बैंक के कर्ज में डूब गईं हैं।

सड़क के लिए संघर्ष, 9 घंटे बाद पामगढ़ चक्काजाम समाप्त

जांजगीर चांपा। डोंगाकोहरौद के ग्रामीणों को 15 साल से खस्ताहाल सड़क की समस्या से अब निजात मिल पाएगा। महिलाओं के नेतृत्व में किए गए चक्काजाम और युवाओं के अनशन के बाद जिला प्रशासन से बातचीत में चार बिंदुओं पर सहमति बनी है।

शुक्रवार को पामगढ़ के अंबेड़कर चौंक में सुबह 10 बजे से डोंगाकोहरौद के लोगों ने चक्काजामकर दिया। इस चक्काजाम का गांव की महिलाओं ने नेतृत्व किया। पामगढ़ के व्यापारियों ने भी ग्रामीणों का साथ दिया और अपनी दुकानें और बाजार बंद कर चक्काजाम को समर्थन दिया।15 वर्षो से बदहाल सड़क को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। चक्काजामके दौरान बारिश भी हुई लेकिन महिलाएं सड़क पर डटी रही।ग्रामीणों के प्रदर्शन और चक्काजाम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। लोगों को समझाने की कोशिश की गई। सुबह से चल रही चर्चा का दौर शाम तक चला, और शाम 7 बजे महिलाओं के सामने जिला प्रशासन के आश्वासन को सुनाया गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग को मानते हुए सड़क मरम्मत कराने के लिए ग्राम पंचायत को 29 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने और आरईएस के माध्यम से काम कराने, भारी वाहनों के प्रवेश मे रोक लगाने, सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने और प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद दिसंबर माह से सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया।

सड़क के लिए जिला प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद डोंगाकोहरौद की महिलाओं ने अनशन पर बैठे युवकों को भी आंदोलन समाप्त करने की समझाईश देने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है। वहीं घंटों के चक्काजाम समाप्त होने के बाद पामगढ़ के व्यवसायिक संस्थान भी देर शाम खुलने लगे।

कोलियारी में अतिक्रमण हटाने की तैयारी से हड़कम्प

धमतरी। तहसील के ग्राम कोलियारी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर माहौल गरमा गया है। करीब 50 मकानों पर बेदखली संबंधी नोटिस चस्पा किए जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप और आक्रोश का माहौल है। एक ओर प्रशासन ने शासकीय भूमि खाली कराने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है, वहीं दूसरी ओर धमतरी विधायक ओंकार साहू ग्रामीणों के समर्थन में गांव पहुंच गए और उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। अतिरिक्त तहसीलदार, धमतरी द्वारा 18 जून 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ग्राम कोलियारी के खसरा नंबर 905 (रकबा 7.71 हेक्टेयर), 906 (0.33 हेक्टेयर) और 907 (0.34 हेक्टेयर) की भूमि छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व में दर्ज है। इसे शासकीय प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया है। प्रशासन ने इन भूमि पर किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण पर रोक लगाते हुए पहले से किए गए

अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने संबंधित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो वह स्वेच्छा से भूमि खाली कर दे। चेतावनी दी गई है कि आगामी निरीक्षण में यदि अतिक्रमण पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने में आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जाएगा। इधर, नोटिस चस्पा होने के बाद गांव के लोगों में गहरी चिंता है।

ग्रामीणों का कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। उन्होंने मेहनत की कमाई से एक-एक ईंट जोड़कर अपने मकान बनाए हैं और अब अचानक बेदखली की कार्रवाई से उनके सामने आशियाना छिनने का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों की जानकारी मिलने पर शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे धमतरी विधायक ओंकार साहू कोलियारी पहुंचे और नोटिस प्राप्त परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर पूरी स्थिति की जानकारी ली। ओंकार साहू ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बारिश के मौसम में किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस समय लोगों को बेदखल किया गया तो वे कहां जाएंगे।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को माना सही

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक प्रताड़ित बुजुर्ग मां के हक में अहम निर्णय सुनाते हुए उसके बेटे और बहू के बेदखली पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा है कि यदि बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो उसे घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने बेटे और बहु की याचिका खारिज करते हुए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के बेदखली के आदेश को सही ठहराया है।कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 केवल भरण पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बुजुर्गों के उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान,शांति और सुरक्षा देना भी है। बिलासपुर मिनोचा कॉलोनी निवासी 93 वर्षीय बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में एक आवेदन पेश किया था। बुजुर्ग महिला का

आरोप था कि उसके मकान के पहले मंजिल पर रहने वाले बड़े बेटे देवेन्द्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना उन्हें लगातार प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने अपने जीवन खत्म करने की आशंका के साथ बेटे बहू को घर से बेदखल करने की गुहार लगाई थी। बुजुर्ग महिला के आवेदन पर जांच परख के बाद मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने 12 सितंबर 2024 को बेटा बहू को घर खाली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ बेटे बहू ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष भी अपील की,वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।अंत में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए बेटे बहू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने भी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया है।

किसानों की तकदीर नाशपाती की खेती से बदली जिन्दगी

नाशपाती की खेती करने वाले किसानों की संख्या जिले में 3500 के पार पहुंच चुकी है. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.

जशपुर। जिला जशपुर को सिर्फ नागलोक के रूप में ही नहीं जाना जाता है, जशपुर जिले को यहां के मेहनतकश किसानों के लिए भी जाना जाता है। यहां के ज्यादातर किसान धान और सब्जियों की खेती करते हैं। लेकिन कम और ज्यादा बारिश की वजह से कई बार इनको फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते यहां के किसान अब तेजी से फलों के खेती की ओर अपना रुख कर रहे हैं। बीते कुछ सालों से उद्यानिकी विभाग की मदद से यहां के किसानों ने नाशपाती की फसल लगाने की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के उत्तर-पूर्वी कोने पर बसा जशपुर अंतिम छोर का जिला है। जशपुर के बाद झारखंड की सीमा शुरू हो जाती है। यहां से ओडिशा राज्य की सीमा भी करीब है। इसलिए लोग जशपुर को झारखंड और ओडिशा के बीच का प्रवेश द्वार भी कहते हैं।

जशपुर के किसानों को अब इसी प्रवेश द्वार का फायदा भी तेजी से मिल रहा है। यहां उगाई जाने वाली रसीली नाशपाती बड़ी मात्रा में बिकने के लिए ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है। नाशपाती की खेती करने वाले किसान कहते हैं कि उनकी आय तो बढ़ ही रही है, उनकी फसल की डिमांड भी कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। किसान बताते हैं कि जशपुर का मौसम नाशपाती की खेती के लिए बेहतरीन है। इस साल भी अच्छी फसल हुई है और रिकार्ड स्तर पर नाशपाती का उत्पादन हुआ है। किसान कहते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में व्यापारी पड़ोसी राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से नाशपाती खरीदने के लिए आ रहे हैं। नाशपाती की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बाजारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। झारखंड और अन्य राज्यों से आने वाले थोक व्यापारी सीधे बागानों तक पहुंचकर पूरी फसल का सौदा कर लेते हैं और मौके पर ही नगद भुगतान कर नाशपाती ले जाते हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम तो मिलता ही है, फसल बेचने के लिए खरीदार नहीं खोजने पड़ते। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक करन सोनकर कहते हैं, जशपुर जिले की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां नाशपाती उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। वर्तमान में जिले के लगभग 3500 किसान नाशपाती की खेती से जुड़े हुए हैं और जिले में हर साल करीब 1500 टन नाशपाती का उत्पादन हो रहा है। किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पौधारोपण, तकनीकी मार्गदर्शन और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

राजस्व और जिला प्रशासन अधिकारियों का तबादला

कलेक्टर ने आदेश जारी कर तहसील कार्यालय सकोला के डीडीओ का प्रभार आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से तहसीलदार पेंड्रा को दिया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जीपीएम कलेक्टर डॉ। संतोष देवांगन ने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों का तबादला किया है। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए ये तबादला सूची जारी की गई है। जिन अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, उसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला राजस्व विभाग के जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल को पेंड्रारोड से स्थानांतरित कर तहसील कार्यालय पेंड्रा में पदस्थ किया गया है। वहीं तहसीलदार प्रीति शर्मा को मरवाही से पेंड्रारोड तथा तहसीलदार अविनाश कुंजुर को पेंड्रा से मरवाही भेजा गया

है।नायब तहसीलदार उमेश कुमार चौहान को पेंड्रा से पेंड्रारोड स्थानांतरित करते हुए उप तहसील बस्ती का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नायब तहसीलदार रमेश कुमार कंभार को मरवाही में यथावत रखते हुए उप तहसील निमधा का अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जिला कार्यालय की जनगणना शाखा में अटैच नायब तहसीलदार अंजली मिश्रा को प्रभारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय सकोला बनाया गया है। वहीं सहायक अधीक्षक दशोदा आर्मो को भू-अभिलेख शाखा में सहायक अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर तहसील कार्यालय सकोला के डीडीओ का प्रभार आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से तहसीलदार पेंड्रा को दिया है। इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावटे को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेजेस, कृषि विभाग, क्रेडा, सी-मार्ट, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, पीएम जनमन योजना तथा बैगा विकास प्राधिकरण का दायित्व सौंपा है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दिलेराम डाहिरे को कानून व्यवस्था, राजस्व अपील एवं पुनरीक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीनीकरण तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी दी गई है।

संयुक्त कलेक्टर निकिता मरकाम को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं एसडीएम मरवाही नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बस्तर की मुरिया संस्कृति का राष्ट्रीय मंच पर गूंजा परचम

जगदलपुर। बस्तर की समृद्ध मुरिया आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक और गौरवशाली उपलब्धि सामने आई है। ग्राम पंचायत आसना जिला बस्तर के युवा आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत कश्यप का चयन टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 8वें ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए हुआ, जिसमें देशभर के चुनिंदा युवा जनजातीय नेताओं ने भाग लिया। बैंगलोर स्थित स्कूल ऑफ एंशियंट विजडम में 21 से 28 जून तक आयोजित इस राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों की 54 से अधिक जनजातियों के 100 युवा प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले नेतृत्व का निर्माण करना था। हेमंत कश्यप का चयन उनके सामाजिक सरोकार, जनहित के मुद्दों पर सक्रिय संघर्ष तथा मुरिया समुदाय की पारंपरिक संस्कृति, लोकनृत्य, वेशभूषा और रीति-रिवाजों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के आधार पर किया गया।

प्रदेश के लाखों मामलों में क्लोजर रिपोर्ट नहीं हुई पेश

बिलासपुर। बिलासपुर-प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्यप्रणाली को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट में पेश आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 लाख 47 हजार 714 मामले ऐसे हैं, जिनमें पुलिस की जांच तो पूरी हो चुकी है, लेकिन साल से उनकी क्लोजर रिपोर्ट (खात्मा/खारिजी रिपोर्ट) सक्षम अदालतों में पेश ही नहीं की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है, और 22 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने कहा है। यह आदेश योगेंद्र बाबू शर्मा की ओर से दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जारी किया। हाई कोर्ट के पिछले कड़े आदेशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने कोर्ट में एक व्यक्तिगत हलफनामा पेश किया। डीजीपी ने स्वीकार किया कि राज्य के कई थानों में वर्षों से मामले लंबित पड़े हैं। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि लंबित मामलों का रिकार्ड इतना बड़ा और भारी-भरकम है कि उसे कागजों ने पर पेश करना मुश्किल था।

पेंड्रा मुख्य मार्ग पर ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, विज्ञापन बोर्ड क्षतिग्रस्त

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पेंड्रा नगर के मुख्य मार्ग पर पंजाब नेशनल बैंक के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोयले से भरा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड से टकराते हुए बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रेलर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर काफी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर कोयला लेकर मोजरबेयर जतहरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान पंजाब नेशनल बैंक के पास चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रेलर पहले विज्ञापन बोर्ड से टकराया और फिर सड़क के बीचोंबीच आकर रुक गया। हादसे में विज्ञापन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया।

जनकपुर की फॉरेस्ट कॉलोनी में घूमते दिखा लकड़बग्घा

एमसीबी। नगर पंचायत जनकपुर की फॉरेस्ट कॉलोनी (लाल बंगला) क्षेत्र में शुक्रवार को एक लकड़बग्घे के दिखाई देने के बाद लोगों में हलचल का माहौल है। जंगल से सटे इस इलाके में वन्यजीव के पहुंचने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने सतर्कता बरतते हुए इसकी जानकारी तत्काल वन विभाग को दी। घटना के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देकर सावधानी बरतने की अपील की है। लकड़बग्घा, कॉलोनी के पहले मोड़ के पास कुछ समय तक घूमता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी है और वन्यजीव की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजा जा सके। जनकपुर रेंजर अतुल तिवारी ने बताया कि लकड़बग्घा सामान्य परिस्थितियों में इंसानों पर हमला नहीं करता। यह प्राय: भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकल आता है और मानव गतिविधि बढ़ने पर स्वयं ही वापस जंगल की ओर लौट जाता है।

मरीजों की मौत के बाद डी.डी. हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन

गौरव जैन, गौरेला। पेण्ड्रा-मरवाही. चिकित्सा के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले और नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे सेमरा स्थित डीडी हॉस्पिटल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। गंभीर लापरवाहियों के चलते दो महिला मरीजों की मौत के बाद कलेक्टर और पर्यवेक्षी प्राधिकारी ने अस्पताल को तत्काल सील करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अस्पताल का पंजीयन (लाइसेंस) भी अस्थायी और सशर्त रूप से निरस्त कर दिया गया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, विकासखंड पेण्ड्रा के ग्राम बेदरचुआ की रहने वाली ज्योति सोनवानी को 11 जून 2026 को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल से सिम्स (SIMS) बिलासपुर रेफर किया गया था। लेकिन संवेदनहीनता की हद पार करते हुए, रास्ते में ही एक एजेंट ने एम्बुलेंस को रोक लिया और मरीज को बहला-फुसलाकर बिना मूलभूत सुविधाओं वाले डी।डी। अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां 11 जून से 16 जून तक मरीज का इलाज अत्यंत लापरवाही पूर्वक किया गया।

कम मानदेय से नाराज कोटवारों का प्रदर्शन

जगदलपुर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर सहित प्रदेशभर में शुक्रवार को कोटवारों ने अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कोटवारों ने शासकीय कर्मचारी का दर्जा, नियमित वेतनमान और मानदेय में वृद्धि की मांग की। कोटवार संघ का कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने तक वे लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन उनकी सेवाओं के अनुरूप उन्हें आज भी

सम्मानजनक मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि गांवों में सूचना प्रसारित करने के लिए मुनादी करना, राजस्व विभाग के कार्यों में सहयोग, पुलिस को सूचना उपलब्ध कराना, पंचायत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व निर्वाचन जैसे विभिन्न विभागों के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना उनकी नियमित जिम्मेदारियों में शामिल है। प्राकृतिक आपदा, कानून-व्यवस्था, शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों में भी कोटवारों की अहम भागीदारी रहती है। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश कोटवारों को केवल 3 हजार से 6 हजार रुपये प्रतिमाह तक का मानदेय दिया जा रहा है। जो वर्तमान महंगाई के दौर में परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संघ के संभागीय अध्यक्ष चतुरराम बघेल ने कहा कि सरकार लगातार कोटवारों से विभिन्न विभागों के कार्य करवा रही है। लेकिन उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जल्द ही कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने, सम्मानजनक वेतनमान लागू करने और अन्य लंबित मांगों का समाधान नहीं करती है। तो प्रदेश स्तर पर बैठक कर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

जनमन योजना की सड़कें 3 महीने में ही उखड़ी, जांच के लिए आदेश

एमसीबी। केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जनमन योजना के जरिए करोड़ों रुपये खर्च कर सड़क निर्माण करा रही हैं। जिले में इस योजना के तहत करीब 200 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें कई का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि कई निर्माणाधीन हैं लेकिन बंजी ग्राम पंचायत में बनी नई सड़कें निर्माण के महज तीन महीने बाद ही सवालों के घेरे में आ गई हैं। ग्राम पंचायत बंजी के दक्षिणपारा और बैगापारा में जनमन योजना के तहत निर्मित सड़कें पहली ही बारिश में अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही हैं। ग्राम पंचायत बंजी के सरपंच देव कुमार और ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की गई और अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया निर्माण किया गया। यही वजह है कि

सड़कों पर जगह-जगह मोटी दरारें उभर आई हैं और कई हिस्सों में सड़क क्षतिग्रस्त होने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि महज दो दिन की बारिश ने निर्माण कार्य की वास्तविकता उजागर कर दी। सड़क किनारे बनाई गई कुछ रिटेनिंग वॉल भी धराशायी हो चुकी हैं। इसके अलावा सड़क के किनारों से मुरूम और मिट्टी बहकर खेतों में पहुंच रही है, जिससे खेती-किसानी प्रभावित हो रही है और बरसात के मौसम में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरुम के ऊपर काफी पतली लेयर ठेकेदार ने बिछाई है। 21 किलोमीटर सड़क में जगह जगह कहीं रिटर्निंग वॉल धंस गया है, दो दिन की बारिश में सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। जहां पुलिया बनना चाहिए वहां ना बनाकर समतल जगह पर बना दिया गया है -देव कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत बंजी जब इस संबंध में पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने मीडिया से मामले की जानकारी मिलने और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

संक्षिप्त समाचार

वित्त मंत्री ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर किया सादर नमन

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने महान राष्ट्रचिंतक, आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत एवं युवाओं के प्रेरणास्रोत की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी विचारों, आध्यात्मिक दृष्टि और राष्ट्रनिर्माण के संदेश से भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को नई दिशा प्रदान की। उनका जीवन आत्मविश्वास, सेवा, चरित्र निर्माण और मानवता के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र और समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके आदर्श आत्मबल, ज्ञान, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करते हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन-दर्शन और उनके विचार सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज बने रहेंगे तथा विकसित और सशक्त भारत के निर्माण के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे।

वित्त मंत्री चौधरी ने पिंगली वेंकैया जी की पुण्यतिथि पर किया पुण्य स्मरण

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' के अभिकल्पक एवं प्रखर देशभक्त पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पिंगली वेंकैया जी का राष्ट्र के प्रति समर्पण और भारतीय तिरंगे के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज केवल भारत की पहचान ही नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिंगली वेंकैया जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, समर्पण और राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका योगदान प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन और देशहित में कार्य करने की प्रेरणा देता है।

नकटी के बाद तुता की बारी! एनआरडीए ने 35 घरों में चस्पा किया नोटिस

रायपुर। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी शांत हुआ नहीं है कि अब राजधानी से लगे तुता गांव में विवाद पैदा हो गया है। नवा रायपुर डेवलपमेंट एथारिटी (एनआरडीए) ने गांव के 35 मकानों पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया है। इसके साथ ही इन मकानों में रहने वालों के बीच दहशत पैदा हो गई है। एनआरडीए द्वारा 30 जून को जारी के नोटिस में ग्रामीणों पर प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। नोटिस में 6 जुलाई तक जवाब देने का समय के साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय पर जवाब नहीं दिया गया तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का तर्क है कि वे इस जगह पर पिछले 25 से 50 वर्षों (दशकों) से रह रहे हैं, और उनकी पूरी पीढ़ी यहीं पली-बढ़ी है। उनका सवाल यह है कि यदि उनका आशियाना अवैध था, तो इतने दशकों तक प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह खामोश क्यों रहा?

ब्रह्मपुर-उधना के मध्य पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रायपुर से गुजरेगी

रायपुर। यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा ट्रेन संख्या 08411 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल का पहली बार संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात के यात्रियों को सीधी एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक एलएचबी कोचों से सुसज्जित है। गाड़ी संख्या 19022/19021 ब्रह्मपुर-उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस जो हफ्ते में 3 दिन चलेगी की पहली बार यात्रा विजयनगरम-टिटलागढ़ -रायपुर -दुर्ग के रास्ते 6 जुलाई को नीचे दी समय सारणी के अनुसार चलेगी। यह ब्रह्मपुर से उधना के लिए एक स्पेशल ट्रेन होगी और इसे 6 जुलाई सोमवार को शाम 17:00 बजे (संभावित) हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। गाड़ी संख्या 08411 ब्रह्मपुर-उधना ब्रह्मपुर स्टेशन से 17.00 बजे रवाना होकर विजयनगरम-टिटलागढ़ होते हुए रायपुर 7:20 बजे, दुर्ग 08:15 बजे, गोंदिया 08.25 बजे, नागपुर 12:00 बजे होते हुए अकोला भुसावल के रास्ते से उधना 02 बजे पहुंचेगी।

धमतरी में माफियाओं पर प्रशासन का सख्त, खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। धमतरी जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के कड़े निर्देशानुसार आज राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टरों को रंगे हाथों जब्त किया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन को लगातार कोलियारी-धमतरी मार्ग पर अवैध रेत परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं। इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए राजस्व और खनिज विभाग की एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने जब मार्ग पर घेराबंदी कर रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को रोका और उनसे खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज (रॉयल्टी पर्ची/अनुमति) की मांग की, तो वाहन चालक कोई भी संतोषजनक कागजात पेश नहीं कर सके।

16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री शर्मा

पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा

■ छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11,664 करोड़ का अनुदान

रायपुर। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कार्यशाला के विभिन्न तकनीकी सत्रों में सहभागिता करते हुए पंचायतों एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर आयोजित प्रस्तुतियों और विचार-विमर्श का अवलोकन किया।

कार्यशाला के दौरान 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित अनुदान की जानकारी साझा की गई। आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि में छत्तीसगढ़ को कुल 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। इसमें 9,331 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट तथा 2,333 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। वहीं, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अंतर-राज्यीय अनुदान वितरण में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 2.68 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

वर्षवार आवंटन के अनुसार 2026-27 में राज्य को 1,498 करोड़ रुपए की बेसिक ग्रांट मिलेगी। 2027-28 में 1,663 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 248 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, 2028-29 में 1,846 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 624 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट, 2029-30 में 2,049 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 693 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट तथा 2030-31 में 2,275 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट एवं 768 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट का प्रावधान किया गया है।

यह अनुदान ग्राम पंचायतों एवं अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से आधारभूत अधोसंरचना के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री आज करेंगे थोक बाजार डूमरतराई फेस-2 का नामकरण एवं लोकार्पण

■ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित समारोह में होंगे शामिल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे अध्यक्षता

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित रायपुर के डूमरतराई थोक बाजार फेस-2 के नामकरण एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन 5 जुलाई 2026 (रविवार) को शाम 5:00 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे।

कार्यक्रम में मंत्री श्री केदार कश्यप, मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

इसके अलावा विधायक श्री राजेश मूणत, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक समारोह में शामिल होंगे।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में

जनसंचार शिक्षा व शोध में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना

रायपुर। जनसंचार शिक्षा व शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में होगी। कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने इसकी विस्तृत कार्य योजना पर अमल करने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार का विशेष दौरा किया।

कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने गुजविप्रौवि के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई से हिसार में एक महत्वपूर्ण बैठक कर उच्च शिक्षा, जनसंचार और शोध को नई दिशा देने के लिए जनसंचार विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर सहमति बनी है। केटीयू, रायपुर (छत्तीसगढ़) और गुजविप्रौवि, हिसार (हरियाणा) के दोनों अग्रणी विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक सहयोग और शैक्षणिक उन्नयन पर विस्तृत मंथन किया गया।

जनसंचार में नया रोडमैप हेतु प्रो. दयाल ने समग्र विकास पर गहन चर्चा की। इसमें अकादमिक, रिसर्च और रणनीतिक बिंदुओं पर सहमति बनी। जनसंचार के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर जोर दिया गया। वैश्विक परिदृश्य और शिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभाग का उन्नयन होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते हुए विद्यार्थी-केंद्रित और नवाचार आधारित अध्ययन प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही मीडिया इंडस्ट्री और अकादमिक क्षेत्र के बीच मजबूत तालमेल स्थापित करने की योजना बनी है। जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में दोनों विश्वविद्यालयों के बीच एक मजबूत साझेदारी के लिए संयुक्त शोध परियोजनाएं तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान-प्रदान के नए अवसर बनेगें।

11 हजार दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण: कवाड़िया

राज्य सरकार की पहल से दिव्यांगजन बनेंगे आत्मनिर्भर उद्यमी, व्यवसाय संचालन और विपणन सहायता भी मिलेगी

रायपुर। प्रदेश के दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम ने बड़ी पहल करते हुए 11 हजार दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री लोकेश कवाड़िया ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) से अधिकृत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री कवाड़िया ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें सफल उद्यमी बनाकर प्रदेश की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के माध्यम से दिव्यांगजन आत्मसम्मान के साथ आजीविका अर्जित कर सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक हितग्राही के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। निगम द्वारा विकसित किए जा रहे प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी दक्षता के साथ वित्तीय प्रबंधन, उद्यमिता विकास तथा व्यवसाय संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे लाभार्थी अपने उद्यम का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें।

श्री कवाड़िया ने कहा कि दिव्यांग उद्यमियों को व्यवसायिक परामर्श, नियमित मार्गदर्शन और विपणन सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। निगम प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है, ताकि लाभार्थी लॉन्ड्री, किराना, रेडीमेड वस्त्र, जूते-चप्पल तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं से जुड़े व्यवहारिक और लाभकारी व्यवसाय स्थापित कर सकें।

बैठक में राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) के मुख्य महाप्रबंधक ने आश्वस्त किया कि सभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत और वितरित किए जाने के बाद एनडीएफडीसी द्वारा पुनर्वित्त (रिफाइनेंस) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी ऋण प्रकरण छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित किए जाएंगे, जिससे हितग्राहियों का समग्र डाटाबेस तैयार किया जा सके तथा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आईडीबीआई बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, एपेक्स बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक तथा एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैंक प्रतिनिधियों ने निगम की पहल की सराहना करते हुए ऋण वितरण प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने का सुझाव दिया।

धान के बदले वैकल्पिक फसलों पर मिलेगी आदान सहायता राशि

■ दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। योजना के तहत खरीफ सीजन में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें लगाने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

योजना के अंतर्गत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, मक्का, कपास तथा कोदो, कुटकी और रागी जैसी मोटे अनाज की फसलों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य धान पर निर्भरता कम करना, दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना तथा भूमि की उर्वरता में सुधार करना है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से यह सत्यापित किया जाएगा कि किसान ने धान के स्थान पर स्वीकृत वैकल्पिक फसल की ही खेती की है। विगत खरीफ सीजन में धान की खेती करने वाले और इस वर्ष वैकल्पिक फसल का चयन करने वाले पात्र किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाएगी।

वहीं जो किसान पहले से खरीफ सीजन में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी अथवा कपास की खेती कर रहे हैं, उन्हें पूर्ववत 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि मिलेगी। योजना का लाभ ट्रस्ट, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों तथा शासकीय संस्थानों सहित अन्य विधिक संस्थाओं को नहीं मिलेगा। कृषि विभाग ने बताया कि पंजीयन के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 एवं पी-2), डीबीटी से लिंक बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से कुंती के सपनों को मिला अपना आशियाना

रायपुर। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नई इबारत लिख रही है। सूरजपुर जिले के दूरस्थ वनांचल ग्राम घुई की निवासी श्रीमती कुंती की कहानी इस बदलाव का प्रेरक उदाहरण है। जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत घुई की 32 वर्षीय श्रीमती कुंती का परिवार लंबे समय तक जर्जर कच्चे मकान में रहने को विवश था। बरसात के दिनों में छत टपकना, घर में पानी भर जाना और आसपास के वन क्षेत्र से जंगली हाथियों के आने का लगातार खतरा परिवार के लिए चिंता और असुरक्षा का कारण बना रहता था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण वे अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी कर किसी प्रकार परिवार का पालन-पोषण करती थीं। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उनका आवास स्वीकृत हुआ।

सभी विस्थापितों को मिलेगा न्याय, नकटी प्रोजेक्ट को 2021 में कांग्रेस सरकार ने दी थी मंजूरी: भाजपा

रायपुर। नकटी विस्थापन मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नकटी में बन रहे आवास सिर्फ विधायकों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आवास अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतमंदों के लिए है।

भाजपा नेता गौरीशंकर ने बताया कि कांग्रेस के समय 2021 में सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही इसे मंजूरी मिली थी। आज 50 लाख के मकान वाले खुद को गरीब बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ढाई साल बाद कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा, सरकार सभी विस्थापितों को उचित आवास और पैकेज देगी। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु मौजूद रहे।

डॉ. नवीन मार्कंडेय ने कहा, कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही। लोगों को गुमराह करके गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन कर रहे। कांग्रेस अपनी करतूत भूल चुकी है। 2020 में कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्क्रिप्ट लिखी, उस समय शासकीय रूप में हाउसिंग बोर्ड ने जमीन मांगी। सारी प्रक्रिया करके शासन को सौंपी गई। कॉलोनी तैयार होने की सूचना पहुंची उस समय तैयार किए गए सर्वे में 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कब्जा मिला, जिसमें कच्चे मकान चिन्हांकित हुए। 2023 में आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ी तब वहां अचानक कब्जाधारियों का रफ्तार बढ़ गया। कब्जा भी बढ़ा। ढाई डिसमिल जमीन आवास के लिए दी जाती है, लेकिन वहां किसी का 10 हजार, किसी का 17 हजार स्क्वेयरफीट मिला।

नवीन मार्कंडेय ने कहा, पिछली सरकार ने जगह का चुनाव किया। लोगों ने वहां आवश्यकता से कई अधिक कब्जा घेर लिया। आज लोगों को गलत दिशा में उकसाया जा रहा। क्या कांग्रेस अवैध कब्जे को सही मानते हैं? पूरे प्रदेश को कब्जा कराना चाहते हैं? कब्जा करके भी कांग्रेस नेता भी जमीन बेच देते हैं। कांग्रेस ने अपनी करतूत छिपाने दूसरे ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, सेरीखेड़ी में कांग्रेस ने कई परिवारों को बेघर किया। कांग्रेस ने उन परिवारों को न जगह दी न विस्थापन दिया। आज घड़ियाली आंशू बहाकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस गरीबी कभी नहीं हटा पाई, सिर्फ षड्यंत्र कर रही। पिछले एक साल नोटिस देते हुए व्यवस्थापन देते हुए बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया पूरी की। 61-62 लोगों या परिवारों को हमने मकान उपल्ब्ध कराया है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना
(प्रथम आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन.आई.टी. क्र./ सिस्टम टेंडर नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू (लाख में)
1	2	3
95/193433	Ordinary Maintanance Work of Various Roads Under Sub Division No.-02, Raipur (C.G.)	रु. 20.00 लाख
99/193510	Special Repair Work of Various Road & Culverts of Vidhansabha Sub-Division, Raipur (C.G.)	रु. 30.00 लाख
114/193771	White Washing, Painting & Distempering in Various Govt. Buildings in Science College Section, Raipur	रु. 20.00 लाख
113/193772	Ordinary Maintenance of Sangwari Vidhayak Vishram Grah, Pankaj Vikram Apartment, Tikrapara GAD Quarters, Residential and Non-Residential Buildings of Ring Road No. 2 Section Under Vidhansabha Sub-Division, Raipur (C.G.)	रु. 15.00 लाख
115/193773	White Washing, Painting & Distempering in Various Govt. Buildings of Ayurvedic College Section, Raipur (C.G.)	रु. 20.00 लाख
117/193774	White Washing, Painting & Distempering in Science College Auditorium Building, Raipur (C.G.)	रू. 20.00 लाख
118/193775	White Washing, Painting & Distempering Work in Various Govt. Buildings of Siliyari Section No-01 & 02, Raipur (C.G.)	रू. 20.00 लाख
119/193776	White Washing, Colour Washing & Distempering Work in Various Govt Building in Heerapur, Dharsiwa 01 & 02, Kabir Nagar & RTO Section, Raipur (C.G)	रु. 30.00 लाख
111/193777	MOW, Special Repair & Addition Alteration Works in Vijeta Complex Section under Vidhansabha Sub Division, Raipur, C.G.	रू. 40.00 लाख
123/194436	Hygiene Maintainance & House Keeping Work at Science college Auditorium Campus, Raipur (Chhattisgarh)	रु. 30.00 लाख

निविदा डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.07.2026 समय सायं 5.30 बजे तक उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड़ की जा सकती है।

जी-262701876/2

अधीक्षण अभियंता-
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मंडल क्र. 1, रायपुर (छ.ग.)

दल-बदल कानून पर पुनर्विचार की जरूरत

संजय कुमार

पश्चिम बंगाल में चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम यह संकेत देता है कि दल-बदल विरोधी कानून पर आज फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नव निर्वाचित विधायकों में से दो-तिहाई से अधिक के दल-बदल करने और लोकसभा में भी तृणमूल कांग्रेस के दो-तिहाई से अधिक सांसदों के दल-बदल कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआइ) में विलय कर लेने के बावजूद दल-बदल की वैधता पर बहस अगर जारी है, तो इसी से इस मामले की गंभीरता समझी जा सकती है। चुनावी नतीजा घोषित होने के बाद दल बदलने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होंगे या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। यह बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग होने वाले नव निर्वाचित विधायकों की संख्या दो-तिहाई से अधिक है, जो तकनीकी रूप से बिना अयोग्यता के पार्टी विभाजन के लिए आवश्यक है। पर इससे इतर चुनावी जनादेश की पवित्रता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बड़ा प्रश्न यह है कि चुनावी नतीजे के बाद नेताओं का मूल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ चले जाने से क्या उन मतदाताओं के साथ धोखा नहीं हो रहा, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी के आधार पर ही चुनाव में वोट दिया था? इसमें कोई संदेह नहीं कि विधायकों और सांसदों के दल-बदल की स्थिति पहले के दौर की तुलना में बेहतर हुई है, जब कोई कानून नहीं था और जनप्रतिनिधि बिना सोचे-समझे रातों-रात पार्टी बदल लेते थे। लेकिन सच बात तो यह है कि अब भी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी में विभाजन किसे कहा जाये। इसलिए इस पर स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है। इस अस्पष्टता को इसलिए भी दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हाल के वर्षों में दल-बदल से जुड़े अधिकांश प्रश्न इसी कारण विवादित रहे हैं कि पार्टी में विभाजन आखिर किसे माना जाये। हर बार जब दल-बदल होता है, तब यह सवाल उठता है कि क्या अलग समूह बना लेना पर्याप्त है या फिर कानून के तहत उस समूह का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस के जिन विधायकों ने दल-बदल किया, उन्होंने एक अलग समूह बनाया है और किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में अपना विलय नहीं किया है। जबकि तृणमूल के लोकसभा सांसदों ने अयोग्यता से बचने के लिए एनसीपीआइ, यानी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में अपना विलय कर लिया। सवाल यह है कि क्या वर्तमान कानून के तहत दोनों स्थितियां वैध हैं। इस मुद्दे पर स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है कि किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय करना अनिवार्य होना चाहिए या फिर अलग समूह के रूप में बने रहना भी स्वीकार्य हो सकता है। दल-बदल विरोधी कानून को बने 41 वर्ष हो चुके हैं। वर्ष 2003 में इसमें एक संशोधन किया गया था, जब एक-तिहाई की शर्त को हटाकर दो-तिहाई कर दिया गया था। मेरा मानना है कि इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए किन बदलावों की आवश्यकता है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह भी सोचा जा सकता है कि क्या इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि जैसे ही कोई निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदले, तो उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाये और उस सीट पर उपचुनाव अनिवार्य हो। इससे नेताओं में व्यक्तिगत लाभ या हित के लिए दल-बदल करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है। निश्चित रूप से यह आसान निर्णय नहीं होगा, लेकिन इस पर विचार तो किया ही जा सकता है।

मोदी का मिशन 360: लोकतंत्र का नया अध्याय

विनोद कुमार सिंह तकियावाला

भारतीय राजनीति में इन दिनों एक शब्द तेजी से चर्चा के केंद्र में है - मोदी महामिशन मिशन 360 ।यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम से किसी आधिकारिक अभियान की घोषणा नहीं की है, फिर भी सत्ता और विपक्ष के राजनीतिक गलियारों में यह धारणा तेजी से मजबूत हो रही है कि भाजपा आगामी वर्षों में संसद के दोनों सदनों में ऐसा संख्याबल अर्जित करने की रणनीति पर काम कर रही है,जिससे न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो, बल्कि संवैधानिक एवं नीतिगत सुधारों को भी अपेक्षाकृत सहजता से आगे बढ़ाया जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल अगले चुनाव की तैयारी नहीं,बल्कि दीर्घकालिक राजनीतिक वर्चस्व की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वही दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चुनौती बताते हुए आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों में राजनीतिक सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है ।सत्य चाहे जो हो,इतना स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति एक नए संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहाँ चुनावी जीत के साथ-साथ संसदीय गणित, गठबंधन प्रबंधन और संवैधानिक व्याख्याएँ भी सत्ता की दिशा तय कर रही हैं ।भारतीय संविधान किसी भी राजनीतिक दल को व्यापक जनादेश प्राप्त करने से नहीं रोकता। लोकतंत्र का मूल आधार ही जनता का विश्वास है ।यदि कोई दल चुनाव जीतकर या वैधानिक गठबंधन के माध्यम से बहुमत प्राप्त करता है तो उसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है ।किंतु जब बहुमत प्राप्त करने की प्रक्रिया विपक्षी दलों में टूट, निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल परिवर्तन अथवा राजनीतिक पुनर्संरेखण के माध्यम से आगे बढ़ती दिखाई देती है,तब लोकतांत्रिक नैतिकता पर बहस स्वाभाविक हो जाती है। यही कारण है कि आज मोदी महामिशन 360 केवल एक राजनीतिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा को लेकर उठ रहे अनेक प्रश्नों का प्रतीक बन चुका है। लोकसभा में साधारण बहुमत सरकार चलाने के लिए पर्याप्त होता है,किंतु संविधान संशोधन जैसे विषयों पर विशेष बहुमत आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनेक संशोधनों के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए तथा कुछ मामलों में आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। इसलिए किसी

भी सरकार के लिए केवल सत्ता में बने रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि संसद में व्यापक संख्याबल भी राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसी संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महिला आरक्षण कानून के पूर्ण क्रियान्वयन, परिसीमन, एक देश- एक चुनाव, प्रशासनिक सुधार तथा भविष्य के अन्य संवैधानिक विषयों को देखते हुए भाजपा अपनी संसदीय शक्ति को और विस्तृत करना चाहती है। ज्ञातव्य रहे कि भारतीय राजनीति में दल-बदल कोई नया अध्याय नहीं है। वर्ष 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल के बार-बार दल बदलने के बाद आया राम, गया राम भारतीय राजनीति का स्थायी मुहावरा बन गया ।इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 में संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। बाद में 91वें संविधान संशोधन (2003) ने इसे और कठोर बनाया।

फिर भी पिछले एक दशक की राजनीति ने यह दिखाया कि कानून होने के बावजूद राजनीतिक पुनर्संरचना पूरी तरह नहीं रुकी ।सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र रहा। पहले शिवसेना में विभाजन हुआ और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी दो हिस्सों में बंट गई ।इन घटनाओं ने केवल सरकार नहीं बदली,बल्कि दल-बदल कानून की व्याख्या, विधानसभा अध्यक्ष की संवैधानिक भूमिका, निर्वाचन आयोग की शक्तियों तथा सर्वोच्च न्यायालय की सीमाओं पर भी व्यापक बहस छेड़ दी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्वाचित जनादेश और संवैधानिक मर्यादा दोनों की रक्षा आवश्यक है, किंतु अनेक परिस्थितियों में अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र से भी जुड़ा रहता है। इससे यह संदेश गया कि आज राजनीतिक लड़ाई केवल विधानसभा या संसद में नहीं, बल्कि न्यायालयों में भी लड़ी जा रही है ।मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन,कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन तथा विभिन्न राज्यों में दल-बदल की घटनाओं ने यह स्थापित किया कि संख्या का खेल अब केवल चुनाव परिणामों से तय नहीं होता, बल्कि चुनाव के बाद की राजनीतिक रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल भी इस बहस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में कई नेताओं के दल बदलने की घटनाएँ सामने आईं। कुछ नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, जबकि बाद में कुछ पुन: वापस लौटे। इन घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारतीय राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता कमजोर हो रही है और चुनावी गणित अधिक प्रभावी बनता जा रहा है। दिल्ली और पंजाब की राजनीति में भी समय-समय पर आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों और नेताओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक अटकलें सामने आती रही हैं ।हालाँकि अधिकाँश मामलों में न तो इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही वे निर्णायक राजनीतिक घटनाक्रम में बदलीं,लेकिन इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक सांसद और प्रत्येक क्षेत्रीय दल भविष्य के सत्ता समीकरण का संभावित हिस्सा माना जा रहा है। यहीं से मोदी महामिशन 360 की चर्चा को बल मिलता है। यदि किसी राजनीतिक दल का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि संसद में इतना व्यापक समर्थन प्राप्त करना हो कि भविष्य के बड़े संवैधानिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा सके, तो स्वाभाविक रूप से उसकी रणनीति केवल चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं रह सकती। यद्यपि भाजपा इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं पर सार्वजनिक रूप से संयमित रुख अपनाती रही है, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई,राजनीतिक दबाव और सत्ता के प्रभाव का उपयोग विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा का तर्क रहा है कि यदि विपक्ष के नेता स्वयं उसके साथ जुड़ते हैं तो वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है और जनता अंतत: चुनाव में इसका निर्णय करती है। यहीं भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है -क्या दल बदलना जनादेश का सम्मान है या जनादेश का पुनर्लेखन? संविधान विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि भारतीय संविधान किसी सांसद या विधायक को आजीवन किसी दल से बंधा रहने का आदेश नहीं देता, किंतु दसवीं अनुसूची का उद्देश्य व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचित जनादेश को बदलने से रोकना अवश्य है। इसलिए यदि कानून की भावना और राजनीतिक व्यवहार के बीच लगातार दूरी बढ़ती है, तो भविष्य में दल-बदल विरोधी कानून की पुर्नसमीक्षा की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीति का मौजूदा दौर केवल सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का नहीं, बल्कि राजनीतिक संगठन क्षमता, नेतृत्व, वैचारिक विस्तार और संसदीय अंकगणित की प्रतिस्पर्धा का भी है। पिछले एक दशक में भाजपा ने स्वयं को केवल एक चुनावी दल के रूप में नहीं, बल्कि देशव्यापी संगठन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तार,दक्षिण भारत में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता,नए सामाजिक समूहों तक पहुंच और क्षेत्रीय दलों के साथ व्यावहारिक गठबंधन उसकी इसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। यदि मोदी महामिशन 360 जैसी कोई सोच वास्तव में अस्तित्व में है,तो उसका आधार केवल विपक्ष को कमजोर करना नहीं,बल्कि पूरे देश में राजनीतिक प्रभाव का विस्तार भी है। इसके विपरीत विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं,बल्कि उसकी अपनी एकजुटता है। विचार धारा, नेतृत्व, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और चुनावी हितों के कारण विपक्षी दलों के बीच स्थायी समन्वय अभी तक मजबूत नहीं बन सका है। कई राज्यों में जो दल राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी हैं, वे राज्य स्तर पर एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं ।ऐसी स्थिति में साझा राजनीतिक रणनीति बनाना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि यदि कोई सांसद या विधायक बार-बार दल बदलने के लिए तैयार हो जाता है,तो इसका कारण केवल सत्ता पक्ष की रणनीति नहीं होती, बल्कि उसके मूल दल का संगठनात्मक असंतोष, नेतृत्व संकट अथवा भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी हो सकती है। इसलिए हर राजनीतिक परिवर्तन को केवल ऑपरेशन कहकर नहीं समझा जा सकता ।कई बार राजनीतिक दलों की आंतरिक कमजोरी भी उसके लिए समान रूप से जिम्मेदार होती है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसी प्रकार देवताओं की आयु का परिमाण भी सौ दिव्य वर्ष समझना चाहिये, तदनुसार पितरों के सौ वर्ष, तीन इजार मानव वर्षों के बराबर होते हैं। इसी तरह देवताओं के सौ वर्ष छत्तीस हजार नानव वर्षों के बराबर होते हैं क्योंकि हमारा एक महीना पितरों के एक दिन के बराबर होता है। और हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इससे निश्चित हुआ कि जिसप्रकार मनुष्यों की आयु का प्रमाण सौ मानव वर्षों का है, इसीप्रकार पितरों का तीन हजार चौर देवताओं का छत्तीस हजार मानव वर्षों का समझना चाहिए।

हम देवताओं के वंशज हैं

सृष्टि के आरम्भ में देवताओं और मनुष्यों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध था, या यूं समझिये कि हमारे गोत्रप्रवर्तक महानुभाव प्राय: देवताओं के ही आत्मज थे। वैदिक-साहित्य का पारायण करने से विदित होता है, कि प्राय: सभी मनुष्यों का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में देवसत्ता से है, जैसे प्रसिद्ध सूर्यवंश और चन्द्रवंश के प्रवर्तक भगवान् सूर्यदेव और चन्द्रदेव हैं इसीप्रकार अन्यान्य वंशों के प्रवर्तक- अंगिरा भृगु आदि भी साक्षात् देवता ही थे। सो देवांशभूत होने के कारण भी हमारे पूर्वज देवताओं के समान आयु वाले होते थे। जब कि देवताओं की आयु 36000 मानव वर्षों के बराबर होती है तो देवताओं के वंशजों की भी न्यूनाधिक इतनी ही आयु हो जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है।

हमने यह सृष्टि के आरम्भ काल की अवस्था बतलाई है, परन्तु ज्यों 2 सृष्टि का विस्तार होता चला गया, त्यों त्यों हमारी धमनियों में बहने वाला वह दिव्य रक्त भी क्रमश: मानव रक्त के विमिश्रण से कम मात्रा में होता गया, इस तरह वह दिव्य आयु भी मानव आयुष्य में परिणत हो गई।

क्रमश: ...

माधव सदाशिव गोलवलकर ने बनाया था आरएसएस को महान संस्थागत शक्ति

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 05 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर का निधन हो गया था। वह मां भारती के अनन्य उपासक, राष्ट्र चिंतक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे। वह आरएसएस के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। बता दें कि वह सबसे अधिक 33 सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे। तो आइए जानते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

नागपुर के पास रामटेक में एक मराठी परिवार में 19 फरवरी 1906 को माधवराव सदाशिव गोलवलकर का जन्म हुआ था। उन्होंने साल 1937 में बीएचयू से एमएससी की डिग्री हासिल की थी। वह राष्ट्रवादी नेता और यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसी कारण से उन्होंने बीएचयू में जंतु शास्त्र पढ़ाते थे। इस दौरान उनको गुरुजी का उपनाम मिला था। वहीं साल 1932 में गोलवलकर की हेडगेवार से मुलाकात हुई और इसी के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर को बीएचयू में संघचालक नियुक्त किया गया।

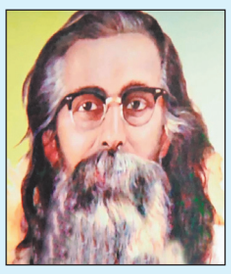

वह आरएसएस के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की मृत्यु के बाद साल 1940 में आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक बने थे। वह हमेशा राजनीति से दूर रहने की सलाह देते थे। क्योंकि गोलवलकर राजनीति को अच्छी चीज नहीं मानते थे।

आज भी आरएसएस और राजनीति के बीच एक लकीर साफ नजर आती है। क्योंकि आरएसएस का सीधे तौर पर कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं रहा है। आरएसएस खुद को हमेशा राजनीति से अलग ही बताता है। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को सशक्त बनाना और संगठित करना है। महाभारत के एक श्लोक में राजनीति को वेश्याओं का धर्म बताया गया है। इसी श्लोक को माधवराव गोलवलकर और उनके बाद सभी सरसंघचालक दोहराते थे।

बता दें कि साल 1940 से लेकर 1973 तक गोलवलकर ने सरसंघचालक का दायित्व बड़ी ही कुशलता से निभाया। सरसंघचालक के तौर पर गोलवलकर के 33 साल बहुत महत्वपूर्ण रहे। इन 33 सालों में भारत छोड़ो आंदोलन, विभाजन के पहले और विभाजन के बाद हुआ भीषण रक्तपात, गांधीजी की हत्या, भारत के संविधान का निर्माण, पंडित नेहरू का निधन, भारत-पाक युद्ध आदि अनेक घटनाएं हुईं। इस दौरान गोलवलकर का अध्ययन और चिंतन इतना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहा कि वह देशभर के युवाओं के लिए प्रेरक पुंज बन गए और पूरे राष्ट्र के दिशा-निर्देशक बन गए थे। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

माधव सदाशिव गोलवलकर ने समाज में रहते हुए एक संन्यासी की तरह अपनी जीवन जिया। वहीं साल 1969 में उनको कैंसर हो गया। जिसके बाद 05 जून 1973 को नागपुर में माधव सदाशिव गोलवलकर का निधन हो गया।

रूस-चीन गुप्त सैन्य प्रशिक्षण ने उड़ा दिए दुनिया के होश

नीरज कुमार दुबे

रूस और चीन के बीच पिछले वर्ष चला गुप्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अब पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के जरिये सामने आए गोपनीय दस्तावेजों और यूरोपीय अधिकारियों के खुलासों ने संकेत दिया है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन केवल कूटनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीनी सैनिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव की व्यक्तिगत मंजूरी प्राप्त थी और इसमें दोनों देशों के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सीधे तौर पर शामिल थे। इन खुलासों ने यूरोप और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है।

हम आपको बता दें कि गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार अगस्त 2025 में बेलोसोव के आंतरिक आदेश के बाद रूसी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा, जहां उसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सैन्य सुविधाओं में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का सबसे संवेदनशील पहलू था रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक सुरक्षा से जुड़ा अभ्यास। नवंबर में बीजिंग स्थित एक सैन्य केंद्र में तीन सप्ताह तक चले पाठ्यक्रम में रूसी सैनिकों को रासायनिक टोही, विकिरण टोही और दूषित वातावरण में सुरक्षा तंत्र बचाने के तरीके सिखाए गए। रिपोर्टों के मुताबिक दस्तावेजों में ऐसे चित्र भी शामिल थे जिनमें चीनी प्रशिक्षक रूसी सैनिकों को मॉडल परमाणु रिएक्टर के सामने प्रशिक्षण देते दिखाई दे रहे थे।

यूरोपीय अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण का महत्व केवल तकनीकी नहीं बल्कि अत्यंत सामरिक है। रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक युद्ध किसी भी आधुनिक सैन्य संघर्ष का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में चीन द्वारा रूस को इस स्तर की जानकारी और अभ्यास उपलब्ध कराना यह

संकेत देता है कि बीजिंग अब यूक्रेन युद्ध से स्वयं को पूरी तरह अलग दिखाने की नीति पर व्यवहारिक रूप से कायम नहीं है। सार्वजनिक मंचों पर चीन लगातार खुद को तटस्थ और शांति मध्यस्थ बताता रहा है, लेकिन इन खुलासों ने उसकी वास्तविक भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक पिछले साल लगभग 200 रूसी सैनिकों को चीन में प्रशिक्षण दिया गया था, जिनमें से कुछ बाद में यूक्रेन युद्ध में भी शामिल हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल शैक्षणिक आदान प्रदान नहीं था, बल्कि युद्धक जरूरतों से सीधे जुड़ा कार्यक्रम था। देखा जाये तो रूस को यूक्रेन मोर्चे पर चार वर्षों से अधिक समय का वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त हो चुका है, जबकि चीन दशकों से किसी बड़े युद्ध में शामिल नहीं रहा है। इसी कारण दोनों देशों के बीच यह साझेदारी पूरक स्वरूप लेती दिखाई दे रही है। चीन रूस से वास्तविक युद्ध अनुभव सीखना चाहता है, जबकि रूस चीन की आधुनिक तकनीक, सिमुलेटर और सैन्य उपकरणों का लाभ उठा रहा है।

हम आपको बता दें कि सामने आये दस्तावेजों में नानजिंग और बेंगबू स्थित प्रशिक्षण केंद्रों का भी उल्लेख है। रूसी रिपोर्टों में चीनी उपकरणों और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता की प्रशंसा की गई, लेकिन साथ ही यह भी दर्ज किया गया कि चीन के पास प्रत्यक्ष युद्ध अनुभव का अभाव है। इससे दोनों सेनाओं के बीच सीखने और सिखाने का दोतरफा समीकरण उभरता है। इस कार्यक्रम में रूस की थल सेना के उप प्रमुख कर्नल जनरल रुस्तम मुरादोव ने रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि चीन की रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक रक्षा अकादमी के प्रमुख मेजर जनरल ली जिनसुन ने एक पाठ्यक्रम के उद्घाटन में भाग लिया। रूसी मेजर जनरल विताली गेरासिमोव भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल रहे। जुलाई में हुए समझौते पर रूसी मेजर जनरल रुस्तम खुसैनोव और चीनी वरिष्ठ कर्नल सुन दायुन के हस्ताक्षर बताए गए हैं।

देखा जाये तो यूरोपीय संघ के लिए यह घटनाक्रम विशेष चिंता का विषय बन गया है। यूक्रेन पर साल 2022 के रूसी आक्रमण के बाद से यूरोप रूस को सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। अब चीन और रूस के बढ़ते सैन्य संबंधों ने ब्रसेल्स को नई रणनीतिक दुविधा में डाल दिया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालास ने दावा किया है कि यूरोप ने अपने स्तर पर इस प्रशिक्षण की पुष्टि कर ली है और इसके निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजिंग ने इन आरोपों को पश्चिमी दुष्प्रचार करार दिया है। इसके बावजूद यूरोपीय देशों के भीतर यह बहस तेज हो चुकी है कि क्या चीन को अब केवल व्यापारिक साझेदार के रूप में देखना पर्याप्त है या उसे रूस के युद्ध प्रयासों का निर्णायक समर्थक मानकर नई नीति बनाई जानी चाहिए?

उधर, यह घटनाक्रम वैश्विक शक्ति संतुलन में उभर रहे नए ध्रुवीकरण को भी उजागर करता है। एक ओर अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन रणनीतिक निकटता बढ़ा रहे हैं। यदि यह सैन्य सहयोग आगे और गहरा होता है तो भविष्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियार विकास और सामरिक खुफिया साझेदारी जैसे नए आयाम भी सामने आ सकते हैं। इससे एशिया और यूरोप दोनों में सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं।

भारत के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली लंबे समय से रूस के साथ पारंपरिक रक्षा संबंध बनाए हुए है, जबकि चीन उसके लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य निकटता भारत के लिए रणनीतिक संतुलन को जटिल बना सकती है। यदि मॉस्को बीजिंग के अधिक करीब जाता है तो भविष्य में भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी, हथियार आपूर्ति और सामरिक सहयोग के स्तर पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर तब, जब चीन पहले से ही हिंद महासागर, दक्षिण एशिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ा रहा है। इतिहास

भारत के नीति निर्माताओं के लिए यह संकेत भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रह गया है। रेडियोलॉजिकल, रासायनिक और जैविक सुरक्षा जैसे क्षेत्र भविष्य की युद्ध रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी सामरिक तैयारियों, वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेष सैन्य प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करना होगा। साथ ही रूस के साथ संबंधों को संतुलित रखते हुए अमेरिका, यूरोप और अन्य साझेदार देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को भी अधिक व्यापक बनाना होगा।

बहरहाल, रूस और चीन का यह गुप्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्फ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत भी है। यह बताता है कि वैश्विक राजनीति अब नए शक्ति समूहों में बंटती जा रही है और आने वाले वर्षों में सामरिक प्रतिस्पर्धा और अधिक तीखी हो सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह समय बेहद सतर्क, संतुलित और दूरदर्शी रणनीति अपनाने का है।

आज का इतिहास

1950 कोरियाई युद्ध-उत्तर कोरियाई औरअमेरिकन बलों के बीच पहली मुठभेड़ में, अप्रस्तुत और अनुशासनहीन अमेरिकी सेना के बल को रौंद दिया गया।
1954 बीबीसी ने पहला टेलीविजन न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया। इसकी अवधि 20 मिनट थी और इसे पहले से बनाकर तैयार किया गया था।
1962 फ्रांस ने अल्जीरिया को स्वतंत्र किया।
1962 अल्जीरिया के ओरान में हुए नरसंहार में 96 लोगों की मौत हुई।
1969 टॉम बोया में केन्याई के विकास मंत्री, की हत्या कर दी गयी।
1975 अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी आर्थर ऐश विंबलडन एकल प्रतियोगिता जीतने वाले पहले अश्वेत थे।
1975 केप वर्डे ने पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यह एक द्वीप देश है जो मध्य अटलांटिक महासागर में दस ज्वालामुखीय द्वीपों के एक द्वीपसमूह को पार करता है।
1977 जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक ने एक सैन्य तख्तापलट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उखाड़ फेंका।
1980 स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ब्योर्न बोर्ग ने अपना पांचवां विंबलडन फाइनल जीता और पहली पुरुष खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पांच बार इना राउंड में चैंपियनशिप जीती।
1986 गुडविल गेम्स मास्को में आयोजित किए गए।
1987 द ब्लैक टाइगर्स ऑफ़ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम ने श्रीलंका की सेना के खिलाफ नेल्लीडीह में पहली आत्मघाती बमबारी की।
1989 यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य ओलिवर नॉर्थ को ईरान-कॉन्ट्रा अफेयर के मामले में दोषी ठहराया गया था।
1995 आर्मेनिया गणराज्य ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता के चार साल बाद अपना संविधान अपनाया था। आर्मेनिया यूरेशिया में दक्षिण काकेशस क्षेत्र में एक पहाड़ी देश है। यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
1999 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तालिबान पर प्रतिबंध की घोषणा।
2003 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निहित होने की घोषणा की।
2004 इंडोनेशिया में पहला राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुआ।
2004 ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबाल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास बनाया।
2006 उत्तर कोरिया द्वारा कथित तौर पर कम से कम सात अलग-अलग बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक आयोजित की।

भगवंत मान सरकार के लिए बूमरैंग साबित होता बेअदबी कानून

राकेश सैन

बूमरैंग आस्ट्रेलिया के मूलनिवासियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वो हथियार है जो लक्ष्य भेदने में असफल होने पर मारने वाले पर ही पलटवार करता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर लाया गया 'जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम' अब यही राजनीतिक बूमरैंग साबित होता दिख रहा है। अकाली दल को घेरने व सिख मतदाताओं को रिझाने के लिए लाए गए इस अधिनियम में खुद सरकार फसी हुई दिख रही है।

पंजाब में साल 2015 के बाद अचानक गुरुद्वारों में व अन्य स्थानों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियों की घटनाओं की अंधेरी सी आ गई। इसको लेकर कई हिंसक आंदोलन व धरना प्रदर्शन भी हुए, जिसमें दो प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई। राज्य में उस समय अकाली दल बादल की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल थे। लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा पनपा जो 2017 बादल सरकार की विदाई का एक कारण बना। उसके बाद कांग्रेस सरकार बेअदबी को लेकर आई और अब चुनावों को नजदीक आते देख आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर दांव खेला। आप का यह पासा उलटा पड़ता दिखाई दे रहा है।

पंजाब की राजनीति में उस समय नया मोड़ आया जब अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गडगज़ ने निर्वाचित विधानसभा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और सदस्यों से यह स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने बिना सलाह के एक पंथ से जुड़ा कानून क्यों पारित किया। संवैधानिक रूप से सदन के अंदर विधायकों द्वारा कही या की गई किसी भी बात को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। वे केवल अध्यक्ष, न्यायालयों और जनता के प्रति ही जवाबदेह होते हैं, लेकिन जत्थेदार गडगज़ ने जनता के इन प्रतिनिधियों के साथ स्कूली बच्चों जैसा व्यवहार किया। सही उत्तर न देने पर उन्हें डांटा और एक महीने के भीतर अपना होमवर्क पूरा करने का आदेश

देकर वापस भेज दिया। इस पेशी के दौरान सामने आया कि कुछ विधायकों ने तो इस कानून का प्रारूप तक नहीं पढ़ा था और बिना पढ़े इन पर हस्ताक्षर कर दिए। जब अकाल तख्त के जत्थेदार ने 'जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम' की कुछ धाराओं व तकनीकी शब्दों के बारे में पूछा, तो कई विधायकों ने इस संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की।

भगवंत सिंह मान इतने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, इसके बावजूद, वे अकाली दल के बुने जाल में आसानी से फंस गए। आम आदमी पार्टी अब ऐसे मोड़ पर है जहां अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लागू करने पर भी उसे परेशानी होगी और लागू न करने पर भी वह मुश्किल में पड़ जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सार्वजनिक रूप से कानून में किसी भी बदलाव से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने स्टैंड पर कोहनीमोड़ लेना पड़ेगा। यदि पार्टी जत्थेदार के सुझावों को खारिज कर देती है तो वह पंथक विरोध के झंझावत में फंस जाएगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि मान सरकार को कानून पारित करने से पहले पंथक धड़ों सहित सभी पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए था। यदि मुख्यमंत्री ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को इस प्रक्रिया में शामिल किया होता तो उसे यह समय नहीं देखना पड़ता। वर्तमान में अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का एसजीपीसी पर पूर्ण नियंत्रण है, जिस पर आरोप हैं कि वह मनमाने ढंग से अकाल तख्त जत्थेदारों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करती है। बादल की यह सुनियोजित रणनीति भगवंत मान के लिए संकट की घड़ी पैदा करने की थी और वे जिसमें सफल रहे। राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक श्री बादल इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। आम सिखों द्वारा बेअदबी विरोधी कानून का हार्दिक स्वागत अकाली दल के खेमे में खतरे की घंटी बजा चुका था। सुखबीर बादल सिख वोट बैंक छिटकने को लेकर चिंतित थे, लेकिन मान सरकार ने अपनी सूझबूझ की कमी से बादल को पंथक एजेंट पर लाभ वाली मुद्रा में ला दिया। कानूनी

भगवंत मान की अकाल तख्त साहिब में पेश होने को लेकर अपनी राजनीतिक मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस कदम ने संवैधानिक मर्यादा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि ज्ञानी जैल सिंह और प्रकाश सिंह बादल को जब बुलाया गया तो वे तुरंत अकाल तख्त साहिब नहीं गए। उन्होंने खुद पेश होने का समय तय किया था। सुरजीत सिंह बरनाला (पूर्व मुख्यमंत्री) और बूटा सिंह (पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री) ने संवैधानिक पदों से हटने के बाद ही गलतियों को माफ करवाने के लिए अकाल तख्त साहिब में पेश होने का रास्ता चुना था। लेकिन न तो मान और न ही उनकी सरकार इतना हौंसला दिखा सकी कि वह अपने पद व संवैधानिक मर्यादा का पालन करवा सके। पूरे प्रकरण में वे एक कमजोर मुख्यमंत्री और उनके विधायक अनाड़ी जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं।

रोचक बात है कि सरकार में 92 विधायक होने के बावजूद कोई प्रबुद्ध संकट प्रबंधक व कुशल मार्गदर्शक नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकरण ने सरकार की राजनीतिक कुशलता व रणनीतिक योग्यता पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। यह अब समय ही बातएगा कि इस राजनीतिक बूमरैंग में आप सरकार के हाथ कितने जख्मी होते हैं।

चीन के साथ संबंधों की राह: दोस्ती का हाथ बढ़ाकर धोखा देना पुरानी फितरत

शिवदान सिंह

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के सम्मेलन में भाग लेने आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजीत डोभाल के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने, संदेहों को दूर करने और संवेदनशील मुद्दों को संतुलित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी। लेकिन, दोनों देशों के बीच संबंधों पर बात करते समय ध्यान देना जरूरी है कि दोनों के बीच सीमा विवाद का लंबा इतिहास रहा है।

अप्रैल 1954 में भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना सम्मिलित था। पर, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए 1962 में भारत पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए 1996 में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि नो मैंस लैंड पर दोनों देशों के सैनिक बगैर हथियारों के गश्त करेंगे। लेकिन, जून 2020 में गलवान में निहत्थे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। इससे दोनों देशों के रिश्ते में गंभीर तनाव आ गया।

पिछले कुछ महीनों से दोनों पक्षों ने संवाद और संपर्क बढ़ाकर संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश तेज की है। दोनों देशों के राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के बीच में यह बातचीत उसी का नतीजा है। दरअसल, दोनों देशों के संबंधों में संदेह उत्पन्न करने में चीन की प्रमुख भूमिका रही है। पंचशील समझौते के बाद अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार, चीन ने अपने पड़ोसी देशों की भूमियों पर धीरे-धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। 1950 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया।

1962 के हमले ने दोनों देशों के संबंधों पर गहरा असर डाला। 1967 में नाथुला पर नाकाम हमला किया, जबकि 2017 में दोकलाम में सड़क निर्माण शुरू किया। इस तरह चीन ने बार-बार भारत को धोखा दिया, जिससे उसके वादे और समझौतों पर संदेह होता है। चीन द्वारा भारत के साथ संबंध सुधारने की पेशकश तथा विश्वास बहाली करके संदेह दूर करने के पीछे भारत की बदलती हुई वैश्विक छवि है। अब भारत ने भारत-चीन सीमा पर आधारभूत ढांचे, सड़कें, पुलों, गुफाओं और संचार के साधनों को उच्चस्तरीय बना दिया है। भारत क्वाड में भी शामिल हो गया है।

दरअसल, दक्षिण चीन महासागर में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए ही क्वाड का निर्माण किया गया है। हिंद महासागर में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए भारत ने निकोबार द्वीप समूह को एक सैनिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई है। चीन के साथ संबंधों पर भारतीय रणनीतिकारों को हमेशा संदेह ही रहा है। पर, अब चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के प्रमुख सदस्यों के रूप में भारत और चीन को विकासशील देशों के बीच एकजुटता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि चीन भारत के साथ सीमा विवादों के बजाय अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन, चीन के साथ हमारे सीमा विवाद बने ही हुए हैं।

वह अरुणाचल प्रदेश पर दावा जताता है। इसलिए, भारत को उसके साथ संभलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती का हाथ बढ़ाकर धोखा देना उसकी पुरानी फितरत है।

अभिषेक पर जांच, ममता बनर्जी पर सियासी आंच

सत्येंद्र प्रताप सिंह

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी पिछले कई वर्षों से विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई, पूछताछ और कानूनी विवादों के केंद्र में रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता हो, जब अभिषेक बनर्जी का नाम किसी न किसी जांच या अदालत की सुनवाई से न जुड़ा हो।

इन मामलों का राजनीतिक असर केवल अभिषेक बनर्जी तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार इन्हें केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा बताती रही हैं। उनका आरोप है कि विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता। ऐसे में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही जांचें केवल कानूनी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बन चुकी हैं।

सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के सोनारपुर में उन पर हुए हमले के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिलने दिया गया और कथित रूप से अस्पताल प्रशासन पर उन्हें जल्द छुट्टी देने का दबाव बनाया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का जवाब हिंसा, धमकी या जांच एजेंसियों के जरिए नहीं दिया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामलों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई।

अभिषेक के खिलाफ कौन-कौन सी जांचें हुईं?

यह समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच, पूछताछ, समन और आपराधिक मुकदमा चार अलग-अलग कानूनी अवस्थाएं होती हैं। किसी मामले में पूछताछ या समन जारी होने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं होता। अभिषेक बनर्जी के मामले में भी अधिकांश जांचें अभी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची हैं।

1- कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामला : यह सबसे चर्चित मामला है। पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों में कथित अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी और सीबीआई ने कई बार अभिषेक बनर्जी

और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। कई समन जारी किए गए और दिल्ली तथा कोलकाता में लंबी पूछताछ हुई। हालांकि अभी तक इस मामले में अदालत द्वारा उनके खिलाफ कोई अंतिम दोष सिद्ध नहीं हुआ है।

2- शिक्षक भर्ती घोटाला : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन जारी किया। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि कथित अवैध धन के प्रवाह का कोई संबंध उनसे या उनके सहयोगियों से है या नहीं। इस मामले में भी जांच जारी है।

3- साइनगेट मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी जांच कर रही है। आरोप है कि कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षरों को लेकर अनियमितता हुई। सीआईडी इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है।

4- चुनावी भाषण और कथित हेट स्पीच : लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कुछ भाषणों को लेकर शिकायत दर्ज होने के बाद सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन भेजा। जांच इस बात को लेकर है कि क्या उनके भाषण चुनावी आचार संहिता या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

5- वॉयस सैंपल मामला : डीजे टिप्पणी मामले में वॉयस सैंपल लेने के लिए बिधाननगर अदालत ने अभिषेक बनर्जी को फिर तलब किया है। पहले वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। सीआईडी उनकी आवाज़ का नमूना लेकर जांच आगे बढ़ाना चाहती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी जांच एजेंसी की प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार किया है।

6- आवास पर पुलिस कार्रवाई : अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस कार्रवाई और तलाशी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। मामला अदालत पहुंचा, जहां कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा। इस मामले में भी अंतिम निर्णय अभी लंबित है।

चुनावी हलफनामे में क्या है? : आधा दर्जन के करीब मामलों का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ सिर्फ दो आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। यह संख्या उन सभी जांचों से अलग है जिनमें केवल पूछताछ या समन जारी हुए हैं।

कुल कितनी जांचें? : यदि सार्वजनिक रिकॉर्ड को आधार माना जाए तो अभिषेक बनर्जी से जुड़े करीब छह प्रमुख जांच या कानूनी प्रकरण सामने आते हैं। इनमें ईडी, सीबीआई और पश्चिम बंगाल सीआईडी की कार्रवाई शामिल है। कई मामलों में उनसे पूछताछ हुई, समन जारी हुए और कुछ मामलों में अदालतों में सुनवाई जारी है।

टीएमसी का पक्ष : तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए बार-बार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि हर चुनाव से पहले या महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान जांच की गति तेज हो जाती है। ममता बनर्जी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुकी हैं कि उनका परिवार किसी भी जांच से नहीं डरता और कानून के मुताबिक सहयोग करता रहेगा।

भाजपा का आरोप : भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वे केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि यदि किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो कानून के अनुसार जांच होना स्वाभाविक है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध नहीं कहा जा सकता।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामलों में जांच, पूछताछ और समन जारी हुए हैं, लेकिन अब तक किसी प्रमुख मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए अंतिम सजा नहीं सुनाई है। अधिकांश मामले अभी जांच, आरोपों की पड़ताल या न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

ऐसे में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही कार्रवाई फिलहाल कानूनी लड़ाई के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी बनी हुई है। आने वाले समय में अदालतों के फैसले और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ही इन मामलों की अंतिम दिशा तय करेंगे।

दलबदल की कहानी निजी जरूरतों के हिसाब से लिखी जा रही

अमिताभ श्रीवास्तव

'प्रोफेशनलिज्म' इन दिनों 'कॉर्पोरेट' जगत का महत्वपूर्ण शब्द बन चुका है, जिस पर हर निजी संस्था में जोर दिया जाता है। यह उत्पादकता और उपयोगिता से भी जुड़ा है। जिसके अनुसार परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव सामान्य माना जाता है। अब यह बात राजनीति में भी दिखने लगी है, जिससे संस्कार और संस्कृति की चिंता बेमतलब हो चली है। महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु, सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हलचल आम है। दलबदल की कहानी निजी जरूरतों के हिसाब से लिखी जा रही है। उसे भावनाओं से जोड़कर देखना एक भूल है।

जब राजनीति सेवा से पेशे का रूप ले चली है, जिसका हिसाब-किताब दिया-लिया जाने लगा है, तब नेताओं से केवल आदर्श आचरण की अपेक्षा रखना अनुचित ही है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना का शिंदे गुट हो या फिर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) में नेताओं का आना-जाना, किसी दल या उसकी विचारधारा से मोहभंग होने का परिणाम नहीं दिखाई देता है।

उसमें परिस्थिति अनुसार पाला बदलना ही सामने आता है। फिर चाहे विधान परिषद के उपसभापति बने सचिन अहीर हों या छह सांसदों का शिवसेना ठाकरे गुट से टूटना और औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे का शिवसेना शिंदे गुट के पैनल से चुनाव लड़ना हो, पार्टी से मोहभंग होने के बीच भविष्य की आशंकाओं का परिणाम है।

जिस पर फिलहाल शीर्ष स्तर से कोई जवाब या रणनीति सामने नहीं है। वैसे हर राजनीतिक दल के काम करने का तरीका देखा जाए तो भिन्न-भिन्न नजर आता है। शिवसेना सेवा को प्राथमिकता देती है और भाजपा राष्ट्रवाद को मुख्य मानती है। वामपंथी दल विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं और समाजवादी गरीबों को प्रमुखता देते हैं।

दलित और मुस्लिम दल अपने समाज के लिए समर्पित होते हैं, जबकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद को आत्मसात कर चलती है। इसके बीच सभी दलों के नेता इधर-उधर आते-जाते रहते हैं। इनमें अधिक वही होते हैं, जो चुनावी राजनीति के आधार पर किसी दल विशेष में टिके रहते हैं और जैसे ही

परिस्थितियां बदलती हैं, वे दूसरी डाल पर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं।

इस स्थिति का शोक मनाया जाए या फिर सहजता से स्वीकार कर लिया जाए, यह दलगत विषय है। कहीं बात गाली-गलौज तक पहुंच जाती है और कहीं संगठनात्मक प्रक्रिया के बाद कुछ अधिक कहने से बचा जाता है। दूसरे शब्दों में, नेताओं की गतिविधियों को नजरअंदाज कर भविष्य की चिंताओं पर विचार किया जाता है।

हालांकि कहीं यह भी स्वीकार कर लिया जाता है कि नेताओं का आना-जाना उनकी अपनी निजी जरूरत ही नहीं, राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना भी है। जिसे वर्तमान में पेशेवर राजनीति का असली चेहरा माना जा सकता है।नए दौर में अनेक नेताओं के लिए राजनीति केवल सेवा, राष्ट्रवाद, विचार, धर्मनिरपेक्षता या समर्पण नहीं है। वह एक पेशे के रूप में बदल चुकी है,

जिसमें पेशेवराना अंदाज आवश्यक हो गया है। यदि किसी दल में चुनावी संभावनाएं क्षीण हो चली हैं तो उसे छोड़ने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह 'कॉर्पोरेट' जगत में उपयोगिता या आवश्यकता पर खरे उतरना ही होता है। अन्यथा विकल्पों पर विचार किया जाता है। राजनीति में निष्कासन नहीं होता है, लेकिन लोकप्रियता कम होने पर नेता को हाशिए पर जरूर ला दिया जाता है।

दूसरी ओर संगठन कमजोर होने पर अच्छे या पेशेवर नेता उससे किनारा करने में संकोच नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में सचिन अहीर के बाद अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उनके पार्टी छोड़ने का कारण विजयी संभावनाओं का क्षीण होना माना गया है।

इससे पहले अहीर के मामले में कुछ ऐसी ही चिंता थी और शिवसेना ठाकरे गुट से अलग होने वाले छह सांसदों के मन में भी यही बात थी। भाजपा के नेता राम कदम ने हाल में अपने एक बयान में साफ किया कि जितने विधायकों ने शिवसेना ठाकरे गुट छोड़ा, वे सभी दोबारा जीतकर विधानसभा आए। इससे स्पष्ट है कि जीत की संभावनाएं किस तरफ अधिक हैं।

इसी बात को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद-प्रवक्ता संजय राऊत दूसरे ढंग से कहते हैं कि जब भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी तो उसके नेता टूट कर दूसरे दलों में जाने लगेंगे। यह भी तय है कि उनमें अधिकतर वही होंगे, जो किसी भी हाल में सत्ता में रहना चाहते हैं या उनकी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य सरकार से निकटता है।

दरअसल जब से राजनीति भी एक पेशा और उससे जुड़ी गतिविधियां व्यावसायिक नजरिये से देखी जाने लगी हैं, तब से नेताओं के किसी भी कदम को स्वार्थ से परे नहीं देखा जाता है। नौबत यहां तक है कि इन दिनों भाजपा के नेता निस्संकोच कहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता जनता का ध्यान रखते हैं और दूसरे दलों से आए नेता भाजपा के नेताओं को संभालते हैं।

इसलिए दलबदल को व्यापक स्वरूप में देखा नहीं जा सकता है। उसके पीछे का जीवन भले ही सार्वजनिक हो, लेकिन चिंताएं निजी ही रहती हैं। यदि इस पर भी दल अपने नेताओं की आवाजाही पर नाराजगी जताएं तो उन्हें यह पहले समझना होगा कि सेवा और विचारधारा के दलीय संस्कार कहां कमजोर पड़ गए। राजनीति में हार-जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

फिर एक तरफ देखने की आदत रखने वाले राजनीतिक जीवन में कैसे आ गए? उन्हें बनाए रखना हर दलों की मजबूरी क्यों हो चली है? क्या राजनीति की नई पौध तैयार नहीं हो रही है, जिसके चलते मजबूरी में समझौते किए जा रहे हैं। स्पष्ट है कि दलबदल की स्थिति में कुंठित होकर अनर्गल प्रलाप करने से बेहतर है कि आत्मचिंतन किया जाए और राजनीति से गुम होती नीति को कहीं खोजने का प्रयास किया जाए। तभी स्थिरता के सपने साकार होंगे और आया राम-गया राम सिर्फ एक कहावत में सिमट जाएंगे।

जब सत्ता के भीतर से उठे सवाल

कुमार कृष्णन

बिहार की राजनीति में कई बार विपक्ष से अधिक असहज सवाल सत्ता के भीतर से उठते हैं। यही इस समय हो रहा है। भोजपुर के भरत तिवारी प्रकरण और राजगीर में दो दलित युवकों की हत्या ने कानून-व्यवस्था पर बहस छेड़ी ही थी, लेकिन इस बहस को निर्णायक मोड़ तब मिला जब केंद्र सरकार के मंत्री और एनडीए के प्रमुख सहयोगी चिराग पासवान स्वयं पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे। भारतीय राजनीति में संवेदना का सबसे बड़ा प्रमाण बयान नहीं, उपस्थिति होती है। घटनास्थल पर पहुंचना केवल औपचारिकता नहीं होता; वह संदेश होता है कि सत्ता जनता की पीड़ा से दूर नहीं है। यही कारण है कि भरत तिवारी के गांव जाकर उनकी मां से मिलना, परिवार को न्याय का भरोसा देना और उसके बाद उसी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना, जिसका वे स्वयं हिस्सा हैं, सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है। चिराग ने भरत तिवारी की मौत को केवल पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं माना। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि यह हत्या है, तो लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने लाइन हाजिर किए गए डीएसपी की पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए और इसे कार्रवाई से अधिक पुरस्कार जैसा बताया। इसके पहले वे अमित शाह से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दे चुके थे। संदेश स्पष्ट था—जांच ऐसी हो जिस पर जनता को भरोसा हो। यहीं राजनीति रोचक भी हो जाती है और गंभीर भी। आमतौर पर गठबंधन सरकारों में सहयोगी दल विवादास्पद मामलों पर संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने संयम और चुप्पी के बीच का अंतर समझाया। उन्होंने सरकार गिराने की बात नहीं की, लेकिन सरकार को आईना जरूर दिखाया। लोकतंत्र में शायद सहयोगी की यही सबसे रचनात्मक भूमिका होती है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में कभी ऐसी परंपरा रही है कि बड़ी घटनाओं के बाद नेता सबसे पहले पीड़ित परिवार तक पहुंचते थे। कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान, यशवंत सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र, जैसे नेता घटनास्थल की राजनीति करते थे, और यह राजनीति नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि जनता के बीच उपस्थित रहने की राजनीति थी। इस पूरे घटनाक्रम में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन की सक्रियता का भी उल्लेख आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने स्वयं को ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है जो किसी भी बड़ी दुर्घटना, हिंसा या प्रशासनिक विवाद के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के बीच मौजूद रहता है। चाहे सड़क दुर्घटना हो, अपराध की घटना हो या सामाजिक तनाव, उनकी राजनीति का एक प्रमुख पक्ष प्रत्यक्ष उपस्थिति रहा है। यदि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी जनता के दुख-दर्द में सहभागी होना है, तो यह परंपरा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए। इस दृष्टि से चिराग पासवान और पप्पू यादव—दोनों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि पीड़ित परिवार के दरवाजे तक पहुंचना केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी है। अंततः जनता भाषणों से अधिक नेताओं की संवेदनशील उपस्थिति को याद रखती है। सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक ओर मुख्यमंत्री और सरकार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का संदेश दे रहे हैं। दूसरी ओर, पुलिस कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। कानून का राज केवल अपराधियों के विरुद्ध सख्ती से स्थापित नहीं होता; वह पुलिस की जवाबदेही से भी स्थापित होता है। यदि पुलिस की कार्रवाई पर संदेह पैदा हो, तो निष्पक्ष जांच सरकार की मजबूरी नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बन जाती है। चिराग पासवान की सक्रियता का राजनीतिक अर्थ भी है। वे पिछले कुछ वर्षों से स्वयं को केवल एक सहयोगी दल के नेता के रूप में नहीं, बल्कि दलित समाज, युवाओं और पीड़ित परिवारों की आवाज़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भरत तिवारी और राजगीर—दोनों मामलों में उनका हस्तक्षेप इसी रणनीति का विस्तार भी माना जाएगा। इससे वे गठबंधन में रहते हुए भी अपनी अलग राजनीतिक पहचान गढ़ते दिखाई देते हैं। सरकार के लिए इस संदेश को समझना आवश्यक है। गठबंधन में असहमति हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार वही सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाती है। लेकिन यदि सहयोगी दल के सवालों को भी केवल राजनीति कहकर टाल दिया जाए, तो इससे जनता के मन में संदेह और गहरा होता है। अंततः यह बहस किसी एक नेता की नहीं, शासन की विश्वसनीयता की है। भरत तिवारी प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, राजगीर के पीड़ितों को न्याय मिले और दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के दायरे में आए—यही लोकतंत्र की पहली शर्त है। राजनीति में भाषण देना आसान है, घटनास्थल तक जाना कठिन। सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त करना आसान है, पीड़ित की चौखट पर बैठकर उसके आंसू पोंछना कठिन।

बारिश में आंखों के इंफेक्शन से बचना हैं तो

जरूर बरतें ये सावधानियां

बारिश के मौसम का मजा लेते समय अपनी आंखों का ध्यान रखना कभी न भूलें क्योंकि इस मौसम में जलवायु संक्रमित सूक्ष्मजीवों को प्रोत्साहित करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक साफ तौलियों का उपयोग कर कंजक्टिवाइटिस, आंखों में गंदगी, सूखापन और कॉर्नियल अल्सर जैसे संक्रमणों से बचना जरूरी है।

ओजोन ग्रुप की मेडिकल कंसल्टेंट उमा सिंह, डॉक्सऐप के मेडिकल ऑपरेशंस के प्रमुख गोवरी कुलकर्णी, जैपलेल में क्रिएटिव हेड शैलजा मित्तल ने आंखों की समस्याओं से बचने के तरीके सूचीबद्ध किए हैं।

» अधिकांश आंखों के रोग आंखों के हाथ से संपर्क में आने पर होते हैं। इसलिए संक्रमण को कम करने या रोकने के लिए आंखों को छूने से पहले हाथ धो लें।

» अपनी आंखों को रगड़ने से बचें क्योंकि संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी बजाए, आंखों के आंसू या गंदगी साफ करने के लिए डिस्पोजेबल टिश्यूज का प्रयोग करें।

» बारिश में भीगने से बचें। हमेशा बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनें।

» अगर आपको में जलन हो, लाल हो या फिर आंखों से पानी गिर रहा हो तो कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग न करें।

» आंखों के आसपास ऐसे मेकअप प्रोडक्ट का यूज न करे जो कि एक्सपायर हो गए हों।

» अपने पर्सनल प्रोडक्ट किसी और से शेयर न करें। रूमाल, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अत्यधिक संक्रामक संक्रमण हो सकते हैं।

बारिश के मौसम का मजा लेते समय अपनी आंखों का ध्यान रखना कभी न भूलें क्योंकि इस मौसम में जलवायु संक्रमित सूक्ष्मजीवों को प्रोत्साहित करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक साफ तौलियों का उपयोग कर कंजक्टिवाइटिस, आंखों में गंदगी, सूखापन और कॉर्नियल अल्सर जैसे संक्रमणों से बचना जरूरी है। ओजोन ग्रुप की मेडिकल कंसल्टेंट उमा सिंह, डॉक्सऐप के मेडिकल ऑपरेशंस के प्रमुख गोवरी कुलकर्णी, जैपलेल में क्रिएटिव हेड शैलजा मित्तल ने आंखों की समस्याओं से बचने के तरीके सूचीबद्ध किए हैं।

» अधिकांश आंखों के रोग आंखों के हाथ से संपर्क में आने पर होते हैं। इसलिए संक्रमण को कम करने या रोकने के लिए आंखों को छूने से पहले हाथ धो लें।

» अपनी आंखों को रगड़ने से बचें क्योंकि संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी बजाए, आंखों के आंसू या गंदगी साफ करने के लिए डिस्पोजेबल टिश्यूज का प्रयोग करें।

» बारिश में भीगने से बचें। हमेशा बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहनें।

» अगर आपको में जलन हो, लाल हो या फिर आंखों से पानी गिर रहा हो तो कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग न करें।

» आंखों के आसपास ऐसे मेकअप प्रोडक्ट का यूज न करे जो कि एक्सपायर हो गए हों।

» अपने पर्सनल प्रोडक्ट किसी और से शेयर न करें। रूमाल, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अत्यधिक संक्रामक संक्रमण हो सकते हैं।

कपड़े और फुटवियर ही नहीं पर्स भी मैचिंग हो तभी बनेगी बात

महिलाएं और लड़कियां चाहे जितनी भी खूबसूरत हों उनकी असली खूबसूरती श्रृंगार के बाद ही निखरती है। इसके लिए जितना संभव हो, वे सजती संवरती हैं। लेकिन सुंदर परिधान, मेकअप और गहनों के साथ मैचिंग पर्स न हो तो सारी खूबसूरती धरी रह जाती है। पर्स या बैग आज के युग में सिर्फ सुंदर दिखने का जारिया ही नहीं स्टेटस सिंबल भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला चाहे हाउस वाइफ हो या कामकाजी या स्कूल-कॉलेज जाने वाली, पर्स या हैंड बैग उनके फैशन के साथ-साथ आम जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आवश्यक है।

जिस तरह कॉलेज की लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के लिए गहने, वस्त्र, सैंडिल आदि जरूरी हैं, उसी तरह हैंड बैग और पर्स भी उनके लिए बेहद जरूरी हैं। इससे व्यक्तित्व को एक अलग लुक तो मिलता ही है, साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी-छोटी चीजों को भी संभाल कर इसमें आसानी से रखा जाता है। इसके अलावा यह उन्हें आधुनिक फैशन की कतार में भी खड़ा करता है। इसलिए जब भी आप पर्स या हैंड बैग खरीदने जाएं तब फैशन के अनुसार उनके चलन, उपयोगिता, डिजाइन और दूसरे उद्देश्य को ध्यान में रखकर खरीदें।

अगर आप कॉलेज जाती हैं और कामकाज से वास्ता रखती हैं, तो निश्चित ही आपको इस तरह के पर्स की आवश्यकता होगी, जिसमें आपके उपयोग का सारा सामान आसानी से आ सके। लेकिन इसके बावजूद इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी हाल में आप का पर्स बड़ा नहीं हो। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उसमें बहुत सारे खाने हों, जिससे आप अपनी जरूरतों का सामान अलग-अलग खाने में रख सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर हर सामान आसानी से निकाल सकें। इसके लिए कैनवास और चमड़े के ऐसे कई बैग बाजार में उपलब्ध हैं जिसमें काफी समान रखा जा सकता है।

पर्स या बैग खरीदते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले तो पर्स का रंग, डिजाइन और आकार आपकी पसंद का हो, साथ ही कीमत का ध्यान भी रखें। पर्स का सही आकार का न होना आपकी शाख्सियत को प्रभावित करता है। अगर आप लंबी हैं तो बड़ा पर्स आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है। आप कंधे पर लटकाने वाला बैग भी ले सकती हैं। अगर आप छोटे कद की महिला हैं तो बड़े साइज के पर्स या बैग हरगिज नहीं लें। छोटे कद की महिलाओं के लिए छोटे पर्स अच्छे और उनके व्यक्तित्व में निखार लाने वाले होते हैं।

आजकल जूट, रैगजीन, फाइबर और नायलॉन के बने पर्स हर वर्ग की महिलाओं की पहली पसंद हैं। शाम के समय सैर पर जाने या पार्टी वगैरह में जाने के लिए आप अलग तरह के फैंसी पर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको कई तरह के डिजाइन, सुनहरे और रूपहले काम के, कढ़ाई वाले मोतियों के काम के तथा सुनहरी चैन वाले पर्स बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। ये पर्स अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। केवल इतने ही बड़े हों कि आपके जरूरतों को पूरा कर सकें।

महिलाएं और लड़कियां चाहे जितनी भी खूबसूरत हों उनकी असली खूबसूरती श्रृंगार के बाद ही निखरती है। इसके लिए जितना संभव हो, वे सजती संवरती हैं। लेकिन सुंदर परिधान, मेकअप और गहनों के साथ मैचिंग पर्स न हो तो सारी खूबसूरती धरी रह जाती है। पर्स या बैग आज के युग में सिर्फ सुंदर दिखने का जारिया ही नहीं स्टेटस सिंबल भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला चाहे हाउस वाइफ हो या कामकाजी या स्कूल-कॉलेज जाने वाली, पर्स या हैंड बैग उनके फैशन के साथ-साथ आम जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आवश्यक है। जिस तरह कॉलेज की लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के लिए गहने, वस्त्र, सैंडिल आदि जरूरी हैं, उसी तरह हैंड बैग और पर्स भी उनके लिए बेहद जरूरी हैं। इससे व्यक्तित्व को एक अलग लुक तो मिलता ही है, साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी-छोटी चीजों को भी संभाल कर इसमें आसानी से रखा जाता है। इसके अलावा यह उन्हें आधुनिक फैशन की कतार में भी खड़ा करता है। इसलिए जब भी आप पर्स या हैंड बैग खरीदने जाएं तब फैशन के अनुसार उनके चलन, उपयोगिता, डिजाइन और दूसरे उद्देश्य को ध्यान में रखकर खरीदें। अगर आप कॉलेज जाती हैं और कामकाज से वास्ता रखती हैं, तो निश्चित ही आपको इस तरह के पर्स की आवश्यकता होगी, जिसमें आपके उपयोग का सारा सामान आसानी से आ सके। लेकिन इसके बावजूद इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी हाल में आप का पर्स बड़ा नहीं हो। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उसमें बहुत सारे खाने हों, जिससे आप अपनी जरूरतों का सामान अलग-अलग खाने में रख सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर हर सामान आसानी से निकाल सकें। इसके लिए कैनवास और चमड़े के ऐसे कई बैग बाजार में उपलब्ध हैं जिसमें काफी समान रखा जा सकता है। पर्स या बैग खरीदते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले तो पर्स का रंग, डिजाइन और आकार आपकी पसंद का हो, साथ ही कीमत का ध्यान भी रखें। पर्स का सही आकार का न होना आपकी शाख्सियत को प्रभावित करता है। अगर आप लंबी हैं तो बड़ा पर्स आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है। आप कंधे पर लटकाने वाला बैग भी ले सकती हैं। अगर आप छोटे कद की महिला हैं तो बड़े साइज के पर्स या बैग हरगिज नहीं लें। छोटे कद की महिलाओं के लिए छोटे पर्स अच्छे और उनके व्यक्तित्व में निखार लाने वाले होते हैं। आजकल जूट, रैगजीन, फाइबर और नायलॉन के बने पर्स हर वर्ग की महिलाओं की पहली पसंद हैं। शाम के समय सैर पर जाने या पार्टी वगैरह में जाने के लिए आप अलग तरह के फैंसी पर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको कई तरह के डिजाइन, सुनहरे और रूपहले काम के, कढ़ाई वाले मोतियों के काम के तथा सुनहरी चैन वाले पर्स बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। ये पर्स अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। केवल इतने ही बड़े हों कि आपके जरूरतों को पूरा कर सकें।

सुझाव

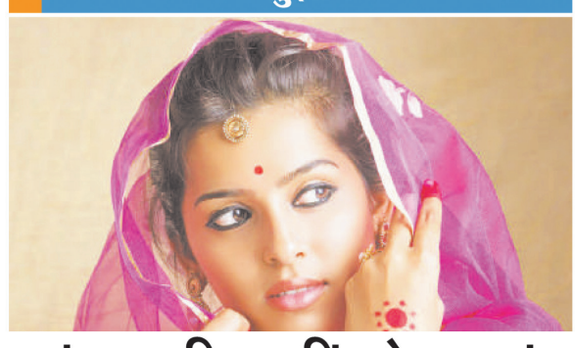

सुंदर ही नहीं सेहतमंद भी बनाती है बिंदी

आमतौर पर महिलाएं ट्रेडिशनल लुक के लिए माथे पर बिंदी लगाती है, लेकिन आप जानती हैं कि माथे की बिंदी आपकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ हेल्थ का भी ख्याल रखती है। शायद आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा । लेकिन यह सच है आइए हम आपको बताते हैं कि बिंदी कैसे आपके सेहत की देखभाल करते हैं। भौंहों को बीच का ये हिस्सा बेहद संवेदनशील होता है। तनाव होने पर सबसे पहले हमारा यही हिस्सा दर्द करने लगता है। और बिंदी तनाव को कम करने में मदद करती है। बिंदी को भौंहों के बीच में लगाते हैं और यहां पर शरीर की सभी नसें एक साथ मिलती है। इसे अग्नि चक्र कहा जाता है। अगर आप बिंदी लगाती है तो आपका मन शांत रहता है और तनाव भी कम महसूस होता है।

झुर्रियां कम आती है

बिंदी लगाने से चेहरे के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इससे मसल्स लचीले और मजबूत होते हैं और झुर्रियां कम आती हैं। इसलिए अगर आपको झुर्रियां आने शुरु हो गई है तो आपको आज से ही बिंदी लगाना शुरु कर दें।

अनिद्रा से बचाएं

अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो आपके लिए बिंदी लगाना काफी फायदेमंद होगी। बिंदी लगाने से शरीर का ऊपरी भाग यानी चेहरा, गर्दन और पीठ के मसल्स को आराम मिलता है। जिससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है।

साइनस से आराम

बिंदी साइनस की समस्या को दूर करने में भी मदद करती है। इस जगह की मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन नाक के आस-पास अच्छी तरह से होने लगता है, जिससे साइनस के कारण होने वाले सूजन कम होती है और नाक खुली जाती है। इससे आपको बहुत आराम महसूस होता है।

आंखों और कानों के लिए बेहतर

अजंता मसल्स को मजबूत बनाने में बिंदी खूब काम आती है। बिंदी को माथे के बीचों-बीच लगाया जाता है और इस जगह की नसें और आंखों की नसों का आपस में गहरा कनेक्शन होता है। जो अगल-बगल देखने और स्पष्ट देखने में मदद करती हैं। इसके अलावा जो नस चेहरे के मसल्स को उत्तेजित करती है । वह कानों के भीतर की मसल्स से मजबूत करके कान को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो क्यों न सेहत से जुड़े इतने फायदों को देखते हुए आज से ही ट्रेडिशन लुक के साथ-साथ वेस्टर्न ड्रेसेज के साथ भी बिंदी को लगाया जाये।

इन तरीकों से सजाएं अपना लिविंग रुम

लिविंग रुम घर का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। यहां परिवार के सभी सदस्य बैठ कर समय बिता सकते हैं। ऐसे में अगर इसकी सजावट अच्छी हो तो महौल भी अच्छा बन जाता है। आप भी अपने लिविंग रूम को खास बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को आपनाएं।

1. दीवारें सजाएं

दीवारों को आप लाइट और डार्क कंबीनेशन के साथ पेंट करवाएं। आप इन पर आर्ट वर्क भी करवा सकते हैं। इससे रुम की लुक अच्छी आएगी।

2. कॉर्नर

लिविंग रूम के हर एक कोने को अच्छे से इस्तेमाल करें। आप कोनों पर कुर्सियां भी लगा सकते हैं।

3. सामान समेट कर रखें

कमरे की सफाई अच्छे से करें और समान को यहां-वहां न बिखरा रहने दें। बच्चों के खिलौने,चाबिया,अखबारें,जूते और बाकी का छोटा-छोटा सामान इस्तेमाल करने के बाद जगह पर रख दें।

4. रोशनी का करें इंतजाम

अगर कमरे में अंधेरा लगता है तो इस कमी को पूरा करने के लिए लाइटिंग की जरूरत है। आप डीजाइनर लैंप के साथ भी इस रूम को सजा सकते हैं। इससे रोशनी भी बढ़ जाएगी और लुक भी अच्छी आएगी।

रेसिपी

मिकस्ड वेजिटेबल्स

सामग्री

पीसकर मुलायम पेस्ट बनाने के लिए,1 कप कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबल-स्पून खड़ा धनिया,8 हरी मिर्च , कटी हुई, 12 लहसुन की कलियां, 4 टी-स्पून ज़ीरा, 4 इलायची, 5 लौंग, 25mm. (1) अदरक का टुकड़ा, 1/2 कप पानी, **अन्य सामग्री,** 3 कप कटी और उबली हुई मिली-जुली सब्जियां (गाजर , फण्सी और हरे मटर), 4 टेबल-स्पून तेल, 4 टेबल-स्पून कटे हुए काजू, नमक स्वादअनुसार, 3/4 कप दुध, 4 टेबल-स्पून फ्रेश क्रीम, 2 चुटकी शक्कर

विधि

गहरी कढ़ाई मे तेल गरम करें, काजू डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट या काजू के सुनहरे होने तक भून लें। छानकर रख दें। उसी तेल में तैयार किया हुआ पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर 1-2 मिनट तक भूने। मिली-जुली सब्जियां, नमक, दुध, क्रीम, शक्कर और तले हुए काजू डालकर अच्छी तरह मिलाएं और बीच-बीच मे हिलाते हुए 3-4 मिनट तक पकाएं। तुरंत परोसें।

स्पिनॅच एण्ड चीज स्टफड क्रैप्स

सामग्री

क्रैप्स् के लिए, 1/4 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप मैदा, 1/4 कप दूध, 1 1/2 टेबल-स्पून पिघला हुआ मक्खन, नमक स्वादअनुसार, मक्खन , चुपड़ने और पकाने के लिए, स्पिनॅच एण्ड चीज भरवां मिश्रण के लिए, 1 कप बारीक कटा हुआ पालक, 1/4 कप कसा हुआ प्रोसेस्ड चीज, 2 टी-स्पून मक्खन, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टी-स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/4 कप बारीक कटे हुए टमाटर, नमक स्वादअनुसार

विधि

क्रैप्स् के लिए: सभी सामग्री को लगभग 3/4 कप पानी के साथ एक गहरे बाउल में अच्छी तरह मिलाकर मुलायम घोल बना लें। एक 100 मिमी (4) व्यास के नॉन-स्टिक पैन को थोड़े मक्खन से चुपड़ लें, 1/4 कप घोल डालकर, पैन को तुरंत गोल घुमा लें जिससे पैन में घोल अच्छी तरह फैल जाए। क्रैप को दोनो तरफ से, थोड़े मक्खन का प्रयोग कर लगभग 30 सेकेन्ड तक पका लें। बचे हुए घोल का प्रयोग कर 4 और क्रैप्स् बना लें। एक तरफ रख दें।

स्पिनॅच एण्ड चीज़ भरवां मिश्रण के लिए: एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में मक्ख़न गरम करें, प्याज और लहसुन डालकर, मध्यम आंच पर 2 मिनट तक भून लें। पालक, टमाटर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर, बीच-बीच में हिलाते हुए, 2 मिनट तक पका लें। चीज़ डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को 5 बराबर भाग में बांटकर एक तरफ रख दें।

आगे बढ़ने की विधि: क्रैप को समतल सूखी जगह पर रखें।

स्पिनॅच एण्ड चीज़ भरवां मिश्रण को क्रैड के बीच रखकर अच्छी तरह रोल कर लें। तुरंत परोसें।

सिगरेट नहीं छोड़ रही पीछा तो खाने शुरू करें ये आहार

स्मोकिंग की बुरी लत आजकल हर 5 में से 3 युवाओं में देखी जाती है। एक बार अगर यह बुरी आदत लग जाए तो छूटनी मुश्किल हो जाती है लेकिन वह इससे होने वाले नुकसान से अंजान है। इससे शरीर को बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इस लत से छुटकारा पाने के लिए अपने आहार में इन चीजों को शामिल करके फायदा मिल सकता है।

1. ओट्स

ओट्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसको खाने से शरीर की चर्बी कम होने के साथ-साथ सिगरेट पीने की आदत को भी दूर हो जाती है। दिन में एक या दो बार इसका सेवन करने से सिगरेट पीने की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके साथ खूब सारा पानी पीएं। धीरे-धीरे सिगरेट पीने की आदत छूट जाएगी।

2. शहद

शहद भी बहुत लाभकारी होता हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन की मात्रा अधिक पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक हनी का रोजाना 1 चम्मच खाने से फायदा मिलेगा।

3. मूली

मूली का सेवन करने से भी धूम्रपान से दूर रहा जा सकता है। इसे सलाद और सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है। यह चेन स्मोकर्स के लिए बहुत लाभकारी है।

4. मुलेठी

मुलेठी का प्रयोग खांसी जैसे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता हैं पर इसके अलावा सिगरेट पीने वालों के लिए यह वरदान हैं। मुलेठी के टुकड़े को मुंह में डालकर चूसने से स्मोकिंग की इच्छा कम हो जाती है। दिन में 1-2 बार मुलेठी का इस्तेमाल जरूर करें।

5. पानी

पानी शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता हैं। इसको पीने से स्किन में चमक आती हैं, विषैले पदार्थ यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हर रोज कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीएं। इससे धूम्रपान की आदत छूटने लगती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राम मंदिर में दिया चंदा वापस लेने कोर्ट जाएंगे दिग्विजय

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में मुकदमा दायर करेंगे और मांग करेंगे कि उनके द्वारा दिया गया चंदा वापस किया जाए, क्योंकि उसका गबन हुआ है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मीडिया से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा, %मैंने तय किया है कि अयोध्या में मुकदमा दायर करूंगा. मैंने जो दान दिया था, उसका गबन हुआ है, उसे लूटा गया है. इसलिए वह पैसा मुझे वापस किया जाए ताकि मैं उसे रामालया ट्रस्ट में जमा कर सकूं. मुझे थाने पर भरोसा नहीं है. पुलिस बीजेपी के नियंत्रण में है, इसलिए मैं थाने नहीं जाऊंगा, अदालत जाऊंगा.दिग्विजय सिंह ने कहा, राम मंदिर के लिए दो बार चंदा अभियान चलाया गया था. पहली बार जब लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी, तब भी मैंने योगदान दिया था. हमें राम मंदिर और भगवान राम पर आस्था है।

भावनाएं आहत करने वाला कंटेंट नहीं चलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को आदेश दिया है कि वह वीडियो हटाने की मांग वाली अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश की किसी भी तरह की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा. यह मामला ध्रुव राठी के इसी साल 21 मार्च को अपलोड किए गए यूट्यूब वीडियो क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं? केरल स्टोरी 2 का पर्दाफाश से जुड़ा है. याचिकाकर्ता वकील अमिता सचदेवा का आरोप है कि इस वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण के बारे में कथित तौर पर कहा गया कि वे मांस और शराब का सेवन करते थे, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि यूट्यूब जैसे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी. उनका तर्क था कि आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाना चाहिए था।

टीएमसी ऑफिस भी गंवा बैठीं ममता बनर्जी

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस में शुक्रवार को एक अहम घटनाक्रम हुआ. टीएमसी के ऋ्रब्रत खेमे ने कोलकाता स्थित पार्टी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया है. ऋ्रब्रत बनर्जी ऑफिस में ताला लगाकर चाबी अपने पास ले गए हैं. इस गुट के नेताओं ने कहा है कि असली टीएमसी वही हैं. शुक्रवार दोपहर को ऋ्रब्रत गुट के नेता मेट्रोपॉलिटन ईएम बाईपास स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय गए और एक बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय को ताला लगा दिया और चले गए. शुक्रवार दोपहर को ऋ्रब्रता बनर्जी, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, जावेद खान, अख्रूज्जमां और अन्य कई नेता अचानक मेट्रोपॉलिटन ईएम बाईपास स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय पहुंचे. पार्टी कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ममता बनर्जी और अरूप रॉय की तस्वीर वाला एक नया पोस्टर भी लगाया गया था. बता दें कि टीएमसी के इस गुट ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है।

क्लाइंट की मंजूरी के बिना वकील नहीं कर सकते समझौता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोई भी वकील अपने मुवक्किल की स्पष्ट और लिखित अनुमति के बिना उसकी ओर से किसी समझौते में शामिल नहीं हो सकता। इस फैसले का असर 37 साल पुराने एक पुश्तैनी संपत्ति बंटवारे के मुकदमे पर पड़ा है, जिसमें अब नए सिरे से ट्रायल शुरू होगा। यह मामला वर्ष 1989 में दायर पुश्तैनी संपत्ति बंटवारे के मुकदमे से जुड़ा है। फरवरी 1994 में, ट्रायल कोर्ट ने पक्षकारों की ओर से संयुक्त रूप से दायर आवेदन के आधार पर समझौता डिक्री पारित की थी, इसके बाद 1997 में अंतिम डिक्री भी जारी हुई थी। हालांकि, करीब 28 साल बाद, एक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों ने इस समझौता डिक्री को यह कहकर चुनौती दी कि उनके पूर्वज ने कभी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और न ही किसी वकील को उनकी ओर से समझौता करने का अधिकार दिया था। उन्होंने वकालतनामा और लिखित बयान के फर्जी होने का भी आरोप लगाया था।

आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के 30 से अधिक सैनिक मारे गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान का ग्वादर जिला शुक्रवार शाम एक भीषण और घातक हमले से दहल उठा, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है। रिपोर्ट के अनुसार, बीएलए ने दावा किया है कि उसके आत्मघाती और अत्याधुनिक हथियारों से लैस लड़ाकों ने ग्वादर के जीवामी स्थित पनवान इलाके में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के एक बड़े कैंप पर हमला किया, जिसमें 30 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।बीएलए ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि इस सबसे खतरनाक और विशिष्ट ऑपरेशन को उनकी मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। संगठन के अनुसार, अताउल्ला बलूच उर्फ ??अजमल नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे एक माजदा ट्रक को कोस्ट गार्ड के भारी सुरक्षा वाले कैंप के भीतर घुसा दिया। स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6ः32 बजे हुए इस आत्मघाती हमले से एक अत्यंत शक्तिशाली धमाका हुआ, जिसने पूरे कैंप को झकझोर दिया। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने दावा किया कि इस विस्फोट के कारण कोस्ट गार्ड का मजबूत कैंप पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया।

संबंधित संपत्तियां कब खरीदी गईं और आरोपी राम मंदिर ट्रस्ट से कब जुड़े

राम मंदिर दान मामले में आरोपियों की संपत्ति जांच तेज, पुलिस को मिले अहम रिकॉर्ड

अयोध्या । अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर दान प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के जमीन और बैंक रिकॉर्ड हासिल किए हैं, इसके बाद अपराध से अर्जित संपत्ति (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की जांच को और तेज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग से आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के भूमि रिकॉर्ड मांगे गए थे, जिसमें से अब तक लगभग 20 भूखंडों से संबंधित दस्तावेज पुलिस को मिल चुके हैं। इन दस्तावेजों का गहन सत्यापन हो रहा है।

जांच दल विशेष रूप से यह ध्यान दे रहा हैं कि संबंधित संपत्तियां कब खरीदी गईं और आरोपियों का राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ाव कब हुआ। इन दोनों तारीखों का मिलान जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि यदि यह सामने आता है कि आरोपियों ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद इन संपत्तियों को खरीदा है और उनके लिए इस्तेमाल हुआ धन का स्रोत संदिग्ध पाया जाता है, तब प्रशासन इन्हें अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके पहले अयोध्या पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर एक वाहन को अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर जब्त किया था। वहीं, जांच एजेंसियों को हाल ही में महत्वपूर्ण तस्वीर भी मिली है, जिसमें दो आरोपी अविनाश और अनुकल्प मिश्रा मंदिर के नकदी गिनती केंद्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर जांच में एक अहम सबूत है, क्योंकि यह आरोपियों को उस कमरे में दिखाती है जहां श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की गिनती और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी होती थी।मामले में अब तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अविनाश और अनुकल्प मिश्रा के अलावा टीनू यादव, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव भी शामिल हैं। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

जयराम रमेश ने केंद्र पर लगाए आरोप

ट्रिपल-इंजन सरकार वोट, सीट और चंदे की चोरी में लगी है

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई गई है।

विपक्षी दलों ने पत्र में चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आयोग की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। जयराम रमेश ने वोटों और सीटों की चोरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बुरी तरह से कम हो गया है।

उन्होंने इस मुद्दे को कथित राम जन्मभूमि चंदा गबन से भी जोड़ा और इसे ट्रिपल-इंजन सरकार के तहत वोट चोरी, सीट चोरी और चंदा चोरी का मामला बताया। उन्होंने एएनआई को बताया, यह एसआईआर प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग के पक्षपातपूर्ण कामकाज से संबंधित विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करता है। यह आज हो रही वोटों और सीटों की चोरी और इस तथ्य से संबंधित है कि लोगों का हमारी चुनावी प्रणाली पर जो विश्वास कभी था, वह बुरी तरह से कम हो गया है।ट

उन्होंने आगे आरोप लगाया %लोगों का मानना है कि चुनाव परिणाम पहले से तय होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा संविधान और हमारी चुनावी प्रणाली खतरे में है। अगर चुनाव परिणाम पहले से ही निर्धारित हैं, तो चुनाव कराने का क्या मतलब है? उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार पाखंड की बीमारी से ग्रस्त हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनका आचरण यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करता है।

जयराम रमेश ने आगे कहा वैसे, अयोध्या में चंदे की चोरी भी हो रही है। यह एक ट्रिपल इंजन सरकार है जहां वोट की चोरी, सीटों की चोरी और चंदे की चोरी होती है।

ये टिप्पणियां तब आईं जब आम आदमी पार्टी और डीएमके सहित इंडिया ब्लॉक की पार्टियां भारत के चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया और चुनाव से संबंधित अन्य मुद्दों पर चिंता जताने के लिए एक साथ आईं। इस गुट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र लिखकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है।

खामेनेई की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब

तेहरान। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए देश-विदेश से गणमान्य व्यक्तियों और हजारों की संख्या में नागरिकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह एक ऐसा क्षण है जिसने पूरे ईरान को शोक और भावुकता में डुबो दिया है, और इस दौरान देश के शीर्ष नेताओं की आंखें भी नम हो गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ को फूट-फूटकर रोते हुए देखा गया, जो देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रव्यापी दुख का प्रतीक था।

आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिन्होंने पिछले तीन दशकों से ईरान का नेतृत्व किया था, का अंतिम संस्कार 3 से 9 जुलाई तक चलने वाले एक विस्तृत कार्यक्रम के तहत किया गया। उनके अंतिम विदाई समारोह में ईरानी नेताओं के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे, जिन्होंने शोक संतप्त राष्ट्र को अपना गहरा दुख व्यक्त किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी कई देशों के मेहमानों ने ईरान पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्केरिटा ने विशेष प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। खामेनेई का निधन 28 फरवरी को तेहरान पर अमेरिका और इज़राइल के हवाई हमलों के पहले दिन हुआ था, जिसने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस दुखद अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। तेहरान के राज्यपाल मोहम्मद सादेग मोतामदियान ने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों की पुष्टि की, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और शोक का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। इस बीच, ईरान के शक्तिशाली सुरक्षा बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के प्रमुख अहमद वाहिदी ने एक कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा और ईरान के आत्मसमर्पण का सपना उसके दुश्मनों के लिए एक सपना ही रह जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

यूरोप में शानदार प्रदर्शन से बढ़ा भारतीय टीम का आत्मविश्वास

बेंगलुरु। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन का मानना है कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2025-26 के यूरोप चरण में टीम के बेहतरीन प्रदर्शन ने आगामी एफआईएच हॉकी विश्व कप और एशियाई खेलों के लिए उसकी तैयारियों को नई मजबूती दी है। फुल्टन ने कहा कि टीम ने सही समय पर अपनी लय हासिल की है और अब दुनिया की किसी भी मजबूत टीम को चुनौती देने का आत्मविश्वास रखती है।

फुल्टन ने कहा कि मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी और पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड्स पर मिली जीत टीम के आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव लेकर आई है। उन्होंने कहा, इस प्रो लीग अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि खिलाड़ियों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है। जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीमों को हराना और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन यह साबित करता है कि यदि हम अपने गेम प्लान पर टिके रहें तो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं।

भारतीय कोच ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दबाव की परिस्थितियों में बेहतर संयम दिखाया और अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता भी विकसित की। फुल्टन के मुताबिक, यही गुण विश्व कप और एशियाई खेलों जैसे बड़े टूर्नामेंटों में भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी टीम के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ लगातार अच्छे नतीजे खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इस प्रो लीग अभियान से हमें काफी आत्मविश्वास मिला है। शीर्ष रैंकिंग वाली टीमों को हराना हमेशा खास होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी मेहनत का परिणाम अब मैदान पर दिखाई देने लगा है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात 16-17% बढ़ाने का लक्ष्य: गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात को बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो लगभग 16-17 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। गोयल ने यहां व्यापार बोर्ड की बैठक में कहा कि सेवा क्षेत्र के निर्यात के लिए 2026-27 में लगभग 470 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, जो करीब 11 प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। व्यापार बोर्ड एक ऐसा मंच है जहां केंद्र, राज्य, निर्यातक और उद्योग प्रतिनिधि देश के व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, हम इस साल कुल निर्यात को एक लाख करोड़ डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वस्तु निर्यात को 442 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर करना होगा। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा।

60 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकता है क्रूड ऑयल

नईदिल्ली। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स के बाद अब दिग्गज अमेरिकी निवेश बैंक सिटीग्रुप ने भी अनुमान जताया है कि साल के अंत तक कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 60 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आ सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को राहत मिलेगी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की संभावना बढ़ सकती है। सिटी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं और इस अहम समुद्री मार्ग पर तेल आपूर्ति फिर से सुचारु हो गई है। पर्याप्त आपूर्ति के चलते दूसरी तिमाही में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 30 प्रतिशत गिरकर लगभग 71.92 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है।

एल्युमीनियम उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) ने सरकार से एल्युमीनियम उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि सस्ते आयात और वैश्विक संरक्षणवाद के बढ़ते दबाव से घरेलू निवेश तथा सरकारी राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है। एएआई ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय एल्युमीनियम उद्योग फिलहाल एक तरफ आयात में तेजी से वृद्धि और दूसरी तरफ निर्यात बाजारों तक पहुंच में कमी जैसी दो समस्याओं से एक साथ जूझ रहा है। संगठन ने आयात में आई तेज़ी को रोकने के लिए बीडीसी बढ़ाने समेत कई ज़रूरी कदम उठाने की मांग की है। एएआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-2026 में एल्युमीनियम आयात रिकॉर्ड स्तर 34.8 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया, जिससे देश से 88,400 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा बाहर गई।

डुकाटी कंपनी ने भारत में लांच की मल्टीस्ट्राडा वी4 रैली

नईदिल्ली। भारत में डुकाटी कंपनी ने अपनी नई 2026 मल्टीस्ट्राडा वी4 रैली लॉन्च कर दी है। यह एडवेंचर टूरर बाइक सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग टेक्नोलॉजी में कई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आई है। इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 32.40 लाख रुपये से शुरू होती है। बाइक में पहले वाला 1,158सीसी वी4 ग्रांटुरिज्मो इंजन दिया गया है, जो 10,750 आरपीएम पर 170 हॉर्सपावर की पावर और 9,000 आरपीएम पर 123 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें रियर सिलेंडर डी-एक्टिवेशन तकनीक भी शामिल है, जो बाइक के खड़े रहने या कम इंजन स्पीड पर पीछे के सिलेंडर को बंद कर देती है, जिससे इंजन की गर्मी कम होती है और ईंधन की बचत भी होती है। चेसिस में भी अहम बदलाव किए गए हैं।

पूर्वी भारत का आर्थिक गौरव लौट सकता है

जीएन बाजपेयी

भारत की आजादी के समय देश का आर्थिक भूगोल आज की तुलना में बिल्कुल भिन्न था। तब उत्तर प्रदेश, अविभाजित बिहार और पश्चिम बंगाल से मिलकर बना पूर्वी क्षेत्र देश की औद्योगिक और वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इस क्षेत्र के पास अधिकांश औद्योगिक आधारभूत संरचना, खनिज संसाधन, रेल नेटवर्क, नदी परिवहन और इंजीनियरिंग क्षमता उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन, वस्त्र निर्माण, चमड़ा उद्योग, कांच और पीतल उद्योग के साथ कृषि उत्पादन में अग्रणी था। कानपुर को वस्त्र मिलों और चमड़ा उद्योग के कारण 'पूरब का मैनचेस्टर' कहा जाता था। वाराणसी, आगरा, मेरठ और मुरादाबाद जैसे शहर भी अपने मजबूत विनिर्माण आधार के लिए प्रसिद्ध थे। तब बिहार कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिजों तथा इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बोकारो, रांची, धनबाद और हजारीबाग जैसे शहर खनन, धातुकर्म और इंजीनियरिंग पर आधारित एकीकृत औद्योगिक तंत्र का निर्माण करते थे। तब पश्चिम बंगाल निस्संदेह देश का सबसे प्रमुख औद्योगिक राज्य था।

कोलकाता भारत का प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र होने के साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और यहां तक कि यूरोप तक व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार था। यह शहर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी का प्रमुख केंद्र भी था। पश्चिम बंगाल जूट, इंजीनियरिंग उत्पादों, रेलवे उपकरणों, भारी मशीनरी, फाउंड्री, रसायन उद्योग तथा चाय व्यापार और निर्यात में अग्रणी था। कोलकाता, हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल और वर्धमान तक फैली औद्योगिक पट्टी भारत के भारी उद्योग की रीढ़ थी। शोधकर्ताओं का

अनुमान है कि 1950-51 में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल से आता था। इस क्षेत्र की एकीकृत अर्थव्यवस्था ने उच्च उत्पादकता सुनिश्चित की। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विकसित औद्योगिक ढांचे ने भारत के व्यापक आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी थी। पूर्वोत्तर, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता अनेक जटिल ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है, जिनमें व्यापक आर्थिक नीतियों की विकृतियां, संरचनात्मक असंतुलन और राजनीतिक परिवर्तन शामिल हैं।

इस गिरावट की शुरुआत 1952 की मालभाड़ा समानीकरण नीति से हुई। इस नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने समानीकरण कोष के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल के लंबी दूरी के परिवहन पर सब्सिडी दी, जिससे खनिज संपन्न राज्यों को मिलने वाला प्राकृतिक भौगोलिक लाभ समाप्त हो गया। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन स्थापित करना था। इसके अंतर्गत कोयला और इस्पात जैसे खनिजों के परिवहन पर सब्सिडी दी गयी। किंतु कपास और तिलहन जैसी अन्य वस्तुओं के परिवहन पर ऐसा नहीं किया गया। उस नीति ने पूर्वी क्षेत्र के कम लागत वाले प्राकृतिक लाभ को समाप्त कर दिया। इससे पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1960-61 के लगभग 10.5 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में केवल 5.6 फीसदी रह गया।

इस झटके को श्रमिक अशांति, आधारभूत संरचना के पतन, कुप्रशासन और तटीय अर्थव्यवस्थाओं के उदय जैसे अन्य कारणों ने और गहरा किया। पूर्वी क्षेत्र उपजाऊ गंगा के मैदानों, विस्तृत रेल और नदी नेटवर्क, कोयला तथा अन्य खनिज संसाधनों, ऐतिहासिक औद्योगिक केंद्रों, विशाल युवा आबादी और बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जैसी प्राकृतिक एवं आर्थिक शक्तियों से संपन्न है। इतिहासकार और अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने कहा था, विकास और अविकास, दोनों संचयी प्रक्रियाएं हैं। पूर्वी क्षेत्र के पुनरुत्थान को भी एक संचयी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां प्रत्येक राज्य को अलग-अलग कर देखने के बजाय पूरे क्षेत्र को एकीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया जाये। इसके लिए व्यावहारिक नीतियों और सहयोगात्मक दृष्टिकोण जरूरी है।

समाचार पचीसा
रायपुर, रविवार 05 जुलाई 2026

चिंतन शिविर 3.0 से सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा तैयार होगी : सीएम साय

■ डिजिटल गवर्नेंस, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि और नेतृत्व विकास पर मंथन

रायपुर। चिंतन शिविर 3.0 का उद्देश्य शासन-प्रशासन को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी नीति-निर्माण की मजबूत आधारशिला तैयार करना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा आईआईएम रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शासन के विभिन्न आयामों पर व्यापक मंथन करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर केवल विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि शासन की कार्यसंस्कृति में निरंतर सुधार और नवाचार का माध्यम बन चुका है। पिछले दो संस्करणों से प्राप्त सुझावों को सरकार ने प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन में तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसरोकारों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना ही इस शिविर का मूल उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर 3.0 के प्रथम दिवस में नेतृत्व विकास, सुशासन, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा कृषि समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक गौर गोपाल दास ने नेतृत्व, भावनात्मक संतुलन, सेवा-भाव और जनप्रतिनिधियों के नैतिक दायित्वों पर अपने विचार रखे। उन्होंने मूल्य-आधारित नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासन को प्रभावी सुशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया।

शिविर में नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विषय पर संबोधित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 5जी, ड्रोन, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तथा डेटा-आधारित प्रशासन के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने तकनीक आधारित सेवा वितरण, नवाचार, रोजगार सृजन तथा डिजिटल समावेशन के लिए छत्तीसगढ़ के समक्ष उपलब्ध अवसरों की भी चर्चा की।

कृषि विषयक सत्र कृषि से समृद्धि में कृषि अर्थशास्त्री डॉ. रमेश चंद तथा कृषि विशेषज्ञ टी. विजय कुमार ने प्राकृतिक खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क और तकनीक आधारित कृषि सुधारों पर अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों ने देश के विभिन्न राज्यों के सफल मॉडलों की जानकारी देते हुए किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। इस दौरान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने समूह आधारित विचार-मंथन में भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई, जिससे फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा सेवा सेतु जैसे महत्वपूर्ण नवाचार भी इसी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम हैं।

नई दिल्ली स्थित आईआईआईडीईएम में आयोजित हुआ एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम

एआई-डीपफेक से निपटेगा चुनाव आयोग, हुआ प्रशिक्षण

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए दूसरे एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तीन जुलाई शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन में देश के 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया नोडल अधिकारी, सोशल मीडिया नोडल अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी तथा राज्य जनसंपर्क विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 260 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ से सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अपर संचालक जनसंपर्क विभाग तथा प्रदेश के सभी 33 जिलों के जिला जनसंपर्क अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही संविधान, निर्वाचन संबंधी कानूनों तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पारदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक एवं फर्जी सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने तथा तथ्यात्मक जानकारी के प्रभावी प्रसार के माध्यम से गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने में मीडिया एवं संचार अधिकारियों की सक्रिय भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत भारतीय मतदाताओं के निर्वाचन प्रणाली पर गहरे विश्वास का परिचायक है।

चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डीपफेक तथा भ्रामक डिजिटल सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों से आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का आह्वान किया। उन्होंने चुनावी साक्षरता क्लबों के माध्यम से युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया।

सम्मेलन में निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित संचार रणनीतियों, मतदाता सूची प्रबंधन, मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया, ईसीआईनेट, संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों, मीडिया प्रबंधन, प्रेस विज्ञप्ति लेखन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग तथा भ्रामक सूचनाओं के प्रबंधन पर विस्तृत तकनीकी एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को समूहों में निर्वाचन प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन कराया गया तथा प्रदर्शनी एवं मीडिया कॉर्नर का अवलोकन भी कराया गया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में चुनाव संपन्न कराने वाले राज्यों के अधिकारियों ने निर्वाचन प्रबंधन एवं जनसंचार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए तथा प्रभावी संचार की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर चर्चा की। सम्मेलन का समापन प्रतिभागियों एवं भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।

नकटी विवाद पर भाजपा की पत्रकारवार्ता

सभी विस्थापितों को मिलेगा न्याय :गौरीशंकर श्रीवास

रायपुर। नकटी विस्थापन मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नकटी में बन रहे आवास सिर्फ विधायकों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आवास अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतमंदों के लिए है।

भाजपा नेता गौरीशंकर ने बताया कि कांग्रेस के समय 2021 में सभी विभागों से हह्रष्ट मिलने के बाद ही इसे मंजूरी मिली थी। आज 50 लाख के मकान वाले खुद को गरीब बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ढाई साल बाद कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक पर्यटन के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा, सरकार सभी विस्थापितों को उचित आवास और पैकेज देगी। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु मौजूद रहे।

डॉ. नवीन मार्कंडेय ने कहा, कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही। लोगों को गुमराह करके गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन कर रहे। कांग्रेस अपनी करतूत भूल चुकी है। 2020 में कांग्रेस की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्क्रिप्ट लिखी, उस समय शासकीय रूप में हाउसिंग बोर्ड ने जमीन मांगी। सारी प्रक्रिया करके शासन को सौंपी गई। कॉलोनी तैयार होने की सूचना पहुंची उस समय तैयार किए गए सर्वे में 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कब्जा मिला, जिसमें कच्चे मकान चिन्हांकित हुए। 2023 में आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ी तब वहां अचानक कब्जाधारियों का रफ्तार बढ़ गया। कब्जा भी बढ़ा। ढाई डिसमिल जमीन आवास के लिए दी जाती है, लेकिन वहां किसी का 10 हजार, किसी का 17 हजार स्क्वेयरफीट मिला।

नवीन मार्कंडेय ने कहा, पिछली सरकार ने जगह का चुनाव किया। लोगों ने वहां आवश्यकता से कई अधिक कब्जा घेर लिया। आज लोगों को गलत दिशा में उकसाया जा रहा। क्या कांग्रेस अवैध कब्जे को सही मानते हैं? पूरे प्रदेश को कब्जा कराना चाहते हैं? कब्जा करके भी कांग्रेस नेता भी जमीन बेच देते हैं। कांग्रेस ने अपनी करतूत छिपाने दूसरे ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, सेरीखेड़ी में कांग्रेस ने कई परिवारों को बेघर किया। कांग्रेस ने उन परिवारों को न जगह दी न विस्थापन दिया। आज घड़ियाली आंशू बहाकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस गरीबी कभी नहीं हटा पाई, सिर्फ षड्यंत्र कर रही। पिछले एक साल नोटिस देते हुए व्यवस्थापन देते हुए बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया पूरी की। 61-62 लोगों या परिवारों को हमने मकान उपलब्ध कराया है।

बस्तर में कृषि विकास को मिलेगी गति: कृषि मंत्री

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने शुक्रवार को बीजापुर कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिलों के कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि अल-नीनो की संभावित परिस्थितियों को लेकर किसानों में किसी प्रकार का भ्रम या भय उत्पन्न न किया जाए। किसानों को वैज्ञानिक सलाह, उन्नत तकनीकों तथा फसल प्रबंधन के माध्यम से बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने उपलब्ध भू-जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए नलकूप, कुएं एवं अन्य सिंचाई साधनों का विस्तार कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने धान के साथ-साथ मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, श्रीअन्न तथा अन्य वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। दंतेवाड़ा जिले में मक्का उत्पादन के सफल मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के निर्देश दिए। श्री नेताम ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में उत्पादित श्रीअन्न के बेहतर विपणन की व्यवस्था विकसित की जाए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन कर आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

आज थोक बाजार डूमरतराई फेस-2 का नामकरण एवं लोकार्पण

■ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित समारोह में होंगे शामिल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी करेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित रायपुर के डूमरतराई थोक बाजार फेस-2 के नामकरण एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन 5 जुलाई 2026 (रविवार) को शाम 5:00 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी करेंगे।कार्यक्रम में मंत्री`दार कश्यप, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब तथा रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, रायपुर महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक समारोह में शामिल होंगे।

स्कूली बच्चों के रेडीमेड गणवेश की गुणवत्ता उच्च स्तरीय

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग द्वारा गोदाम स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से रेडीमेड गणवेश का शत-प्रतिशत कड़ा गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। इसके उपरांत ही स्कूलों में गणवेश की आपूर्ति की जाती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले, विकासखंड या स्कूल/संकुल से ऐसी शिकायत नहीं है कि गणवेश गुणवत्ता विहीन है द्य छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग द्वारा गणवेश की गुणवत्ता की शत-प्रतिशत जांच के बाद ही स्कूलों को आपूर्ति की जाती है।लोक शिक्षण संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश के किसी भी जिले या स्कूल से गणवेश की गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित (ग्रामोद्योग विभाग) विभाग के द्वारा संघ के गोदाम प्रभारियों और तकनीकी टीम के प्रतिवेदन में भी गणवेश की गुणवत्ता को पूरी तरह मानक के अनुरूप पाया गया है। शासन की मंशानुरूप कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए यह रेडीमेड गणवेश राज्य के स्थानीय बुनकरों से तैयार कराए जा रहे हैं और महिला स्व- सहायता समूहों के माध्यम से इनकी सिलाई कराई जा रही है।

उर्वरकों की कालाबाजारी पर राज्य सरकार का जीरो टॉलरेंस

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को समय पर, उचित मूल्य पर और गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ सीजन 2026 के दौरान किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित 275 बोरी यूरिया जब्त कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देश तथा कृषि विभाग के उप संचालक मोरध्वज डडसेना के मार्गदर्शन में गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा जिलेभर में लगातार औचक निरीक्षण और छापामार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर अनुचित लाभ कमाने के प्रयासों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।इसी अभियान के तहत प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर उड़नदस्ता दल ने ग्राम जानो, तहसील देवकर में अँजोर वर्मा के परिसर में औचक निरीक्षण किया।

तेजस कार्यशाला का सफल आयोजन

रायपुर। सुकमा जिले में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तत्वावधान में शबरी ऑडिटोरियम में एक दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य जिले में नवाचार, एक जिला-एक उत्पाद , फूड प्रोसेसिंग और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में महिला स्व-सहायता समूहों, एमएसएमई उद्यमियों, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों सहित लगभग 350 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला पंचायत सुकमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुंद ठाकुर ने कहा कि सुकमा में कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक और नवाचार अपनाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

सहकारिता सप्ताह में कृषक संगोष्ठी आयोजित

रायपुर। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को दंतेवाड़ा जिले के संयुक्त कलेक्टरेट भवन के सभाकक्ष में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री चैतराम अटामी थे। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक श्री अटामी ने कहा कि सहकारिता की भावना ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि की मजबूत नींव है। उन्होंने किसानों से खेती के इस महत्वपूर्ण मौसम में आपसी सहयोग से रोपाई और अन्य कृषि कार्य समय पर पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों की कमी की समस्या दूर होगी और खेती की लागत कम होने के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने अनुभवी किसानों के मार्गदर्शन में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक और प्राकृतिक खेती से उत्पादन बढ़ने के साथ भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है।उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं।

बीरगांव नगर निगम की बड़ी उपलब्धि

300+ गरीब परिवारों के पक्के आवास बनकर तैयार

रायपुर (बीरगांव)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शहरी निर्धन परिवारों को स्वयं का आवास उपलब्ध करने की जो पहल छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है उसमे बीरगांव नगर निगम में सर्वाधिक 300+ परिवारों को आवास प्रदान कर राज्य के नगरीय निकायों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता के सतत निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 'मोर जमीन-मोर मकान' घटक के तहत 300 हितग्राहियों के पक्के आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

नगर पालिक निगम बीरगांव के आयुक्त श्री युगल किशोर उर्वशा ने इस उपलब्धि के लिए उप मुख्यमंत्री श्री साव व विभागीय सचिव के सतत मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताते हुए निगम के अधिकारी कर्मचारियों एवं मैदानी अमले की सराहना की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, जिनके पास स्वयं का भूखंड उपलब्ध था। शासन द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता एवं निगम प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग, तकनीकी मार्गदर्शन तथा समयबद्ध क्रियान्वयन व निरंतर जागरूकता

कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 300+ परिवारों के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास तैयार हो चुके हैं। इन हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी अतिशीघ्र एक गरिमामय समारोह में होगा ।

आयुक्त श्री उर्वशा ने आगे बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्माण चरण की जियो-टैगिंग की गई। निर्माण प्रगति के सत्यापन के उपरांत हितग्राहियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से समय पर किस्तों की राशि हस्तांतरित की गई। समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध होने से हितग्राहियों ने निर्धारित अवधि में अपने आवासों का निर्माण पूर्ण किया।उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन तथा उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देशन में प्रदेश में शहरी गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता के मार्गदर्शन में योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आयुक्त श्री उर्वशा ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि यह उपलब्धि न केवल गरीब एवं आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

मानसून में देरी से घबराएं नहीं, समय पर करें धान की बोआई-रोपाई : कृषि वैज्ञानिक

रायपुर। प्रदेश में इस वर्ष मानसून सामान्य से कुछ देर से पहुंचा है, लेकिन किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी भी धान की खेती के लिए पर्याप्त समय है। मौसम को देखते हुए किसानों को कुछ जरूरी कृषि सलाह जारी की गई है।वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून लगभग 10 दिन देर से आया। जून माह में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत कम वर्षा हुई, लेकिन अब प्रदेश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई तक राज्य में अच्छी वर्षा होने की संभावना है।

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि किसान 15 जुलाई तक धान की सीधी बुआई तथा 30 जुलाई तक रोपाई और बियासी का कार्य कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश थोड़ा विलंब भी हो जाए और हरेली (12 अगस्त) तक बोआई-रोपाई करनी पड़े, तब भी फसल पर अधिक असर नहीं पड़ेगा।

मानसून में देरी को देखते हुए किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, जैसे इन्द्रावती, बस्तर धान-1, छत्तीसगढ़ बारानी धान, इंदिरा एरोबिक धान, एमटीयू-1010, एमटीयू-1153, एमटीयू-1156, एमटीयू-1001, छत्तीसगढ़ धान-1919, छत्तीसगढ़ तेजस्वी धान और महामाया का उपयोग करने की सलाह दी गई है। किसानों से कहा गया है कि बुआई से पहले बीज का फफूंदनाशक दवा से उपचार अवश्य करें और जैव उर्वरकों का भी उपयोग करें। इससे फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन बढ़ता है।

वैज्ञानिकों ने बताया कि धान की सीधी बुआई में खरपतवार (खरपतवार/घास) बड़ी समस्या होती है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसलिए बुआई के बाद पहले 40 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। इसके लिए हाथ से निंदाई, पैडी वीडर या कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित खरपतवारनाशकों का उपयोग किया जा सकता है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.